लखनऊ
शुक्रवार, 7 अगस्त , 2026
वर्ष : 11 । अंक: 338
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8
UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक
आर्यावर्त क्रांति

धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन दुआएं कमाने से ख़ुशी और प्यार आता है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi
NIGHT 28° Low

संक्षेप

दीपके बोले छात्रों को मिला हक अब युवाओं की बारी, सरकार को देनी ही होगी नौकरी

नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की कोर टीम की बैठक के बाद संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी अब केवल युवाओं की व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि CJP आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे को देशव्यापी जनआंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार के सवाल पर संगठित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभिजीत दीपके ने कहा कि हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि रोजगार का मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भी भाग लिया, जिससे यह साबित हुआ कि रोजगार की समस्या समाज के हर वर्ग के युवाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने इसे युवाओं की एकजुटता और लोकतांत्रिक आवाज का मजबूत उदाहरण बताया। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, हम इसे देशव्यापी मुद्दा बनाएंगे। शिक्षा में सुधार के लिए काम करेंगे। स्कूली शिक्षा के समय से ही शिक्षा महंगी रही है। शिक्षा का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। लेकिन हम इसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीजेपी का उद्देश्य बेरोजगारी के सवाल को हर राज्य और हर जिले तक पहुंचाना है। इसके लिए संगठन विभिन्न स्थानों पर बैठकें, जनसंवाद, युवा सम्मेलन और जनजागरण अभियान आयोजित करेगा। उनका मानना है कि जब तक रोजगार के मुद्दे पर व्यापक जनदबाव नहीं बनेगा, तब तक प्रभावी समाधान निकलना कठिन होगा।

यौन उत्पीड़न केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, पूर्व तहलका संपादक ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

मुंबई। वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने तेजपाल को दुष्कर्म और महिला की मर्यादा भंग करने का दोषी ठहराया है। वहीं, इस मामले में कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले पर तरुण तेजपाल ने कहा, 'हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वे राजनीतिक बदले की भावना और तहलका के काम की वजह से मेरे पीछे पड़े हैं। हमने ट्रायल कोर्ट में 7 .5 साल तक केस लड़ा और बरी हो गए। जो लोग उनके साथ हैं, वे बरी हो जाते हैं, लेकिन वे उनके पीछे पड़ते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा। उमर खालिद और शरजील इमाम कई वर्षों से जेल में हैं। तहलका की रिपोर्टिंग से शायद उन्हें कुछ राजनीतिक नुकसान हुआ हो या उनके निजी हितों को चोट पहुंची हो। वे पिछले 13 वर्षों से बदले की भावना से मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि ऐसे जज होंगे जो सच देखेंगे। हम सबूत सबके सामने रखेंगे'। यह मामला 2013 में एक महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, जिसने देशभर में काफी चर्चा बटोरी थी।

रोजगार को केवल नौकरी से जोड़कर देखना गलत, समाज को सोच बदलनी होगी: मोहन भागवत

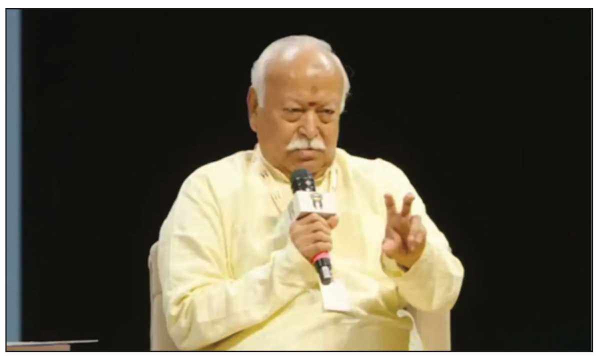

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को Gen Z और Gen Alpha छात्रों से संवाद के दौरान बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। मोहन भागवत ने कहा कि अक्सर काम करने वालों को कमतर समझा जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा करते हैं।

उन्होंने एक पान बेचने वाले का उदाहरण देते हुए समझाया कि उसने किस तरह कड़ी मेहनत करके ₹29 लाख की संपत्ति जमा कर ली थी। मोहन भागवत ने कहा कि हर किसी के लिए सरकारी नौकरी पाना मुमकिन नहीं है और न ही बिना कड़ी मेहनत के पैसे की उम्मीद करना सही है। बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब हम नौकरियों को 'बड़ी' या 'छोटी' के तौर पर आंकना बंद कर देंगे। ऐसा करने से ही ये मुद्दा खत्म हो पाएगा।

संघ प्रमुख ने कहा कि सिर्फ रोजगार ही नौकरी नहीं है। हाथ से काम करने वाले भी पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने एक किसान का उदाहरण देकर इसे समझाया। भागवत ने कहा कि एक किसान के पास 4 लाख रुपये का अनाज है। लेकिन हम अमीर हैं और हमारे पास इतना कैश है तो उसे कुछ नहीं समझा जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को हाथ से जुड़े काम पर भी ध्यान देना चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत

शिक्षा व्यवस्था और प्रोटेस्ट पर पूछे गए सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि आंदोलन भी बातचीत का ही एक रूप है। वरना, यह सिर्फ एक बहस बनकर रह जाता है। उन्होंने कहा कि जब लोग बातचीत करते हैं, तो अच्छे नतीजे निकलते हैं। लोकतंत्र में, आंदोलन आम सहमति बनाने का एक जरिया होते हैं। जब लोगों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो आंदोलन का रास्ता अपनाना एक विकल्प बन जाता है। Gen Z की शिकायतें सही हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है, और इसके लिए बातचीत जरूरी है।

Gen-Z से बात न होने पर हुआ आंदोलन

इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मुंबई में Gen-Z और Gen-Alpha के साथ एक घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि Gen-Z और Gen-Alpha पुरानी पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा देशभक्त और ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत न होने की वजह से ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उन्होंने ये बातें मुंबई में IIMUN (इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस) की 15वीं सालगिरह के मौके पर कहीं। इस कार्यक्रम में 11 से 19 साल की उम्र के लगभग 2,000 छात्र शामिल हुए।

विकसित भारत के निर्माण में प्रादेशिक सेना की भूमिका महत्वपूर्ण : राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य विषय प्रादेशिक सेना रहा, जिसमें बल की भूमिका, दायित्व, उपलब्धियों और भविष्य में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को प्रादेशिक सेना के अधिदेश, संचालन व्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में उसके योगदान की विस्तृत जानकारी दी। समिति के सदस्यों ने बल को और सुदृढ़ करने तथा इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां नियमित सशस्त्र बल देश की सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, वहीं प्रादेशिक सेना सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीय सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दे रही है। उन्होंने प्रादेशिक सेना को नागरिक-सैनिक अवधारणा का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि इसके सदस्य सामान्य नागरिक जीवन में अपने-अपने पेशों में कार्यरत रहते हुए भी आवश्यकता पड़ने पर वर्दी पहनकर सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं।

प्रतापगढ़ बारिश से जुड़ी त्रासदी में एक्शन में मुख्यमंत्री योगी

पीड़ित परिवारों को 4 लाख का मुआवज़ा और उचित इलाज के निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ में हाल ही में बारिश से जुड़ी घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद जारी की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए, प्रतापगढ़ के ज़िला मजिस्ट्रेट ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख सौंपे। राज्य की तत्काल राहत उपायों के तहत प्रभावित परिवारों को कुल 26.20 लाख की अनुग्रह राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि घटना में घायल सभी लोगों को सही समय पर उचित इलाज मिले। ज़िला प्रशासन को पीड़ितों को हर संभव मदद देने और उनकी स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। प्रतापगढ़ में बारिश से जुड़ी एक भयानक घटना के बाद यह आर्थिक मदद दी गई। वहां मॉनसून की बारिश के कारण एक सदी पुराना घर ढह गया, जिससे एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें दो छोटे बच्चे भी शामिल थे। परिवार का इकलौता जीवित सदस्य, एक 28 वर्षीय व्यक्ति, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है। यह घटना उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी उन कई घटनाओं में से एक थी, जिनमें भारी बारिश के कारण दीवारें गिरने और अन्य हादसे हुए, जिससे राज्य में मरने वालों की कुल संख्या नौ हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद देने के लिए मुआवज़े की राशि प्राथमिकता के आधार पर जारी की गई।

खड़गे की अमित शाह से मांग

छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में दें बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर राज्यसभा में बयान देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय पर सदन में चर्चा से बच रही है।

राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने सभापति से अनुरोध किया कि वे गृह मंत्री को सदन में आकर इस मामले पर बयान देने का निर्देश दें। उन्होंने कहा, 'हम देश और उसके 140 करोड़ लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दें। हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।'

खड़गे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भी संसदीय लोकतंत्र में कार्यवाही में व्यवधान को एक स्वीकार्य संसदीय प्रक्रिया बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है तो सरकार जवाब देने से बचने की कोशिश करती है।

रिजिजू ने दिया जवाब

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खड़गे की मांग का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ने अपनी मांग के समर्थन में किसी संसदीय नियम का हवाला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि सरकार की ओर से कौन-सा मंत्री सदन में जवाब देगा।

रिजिजू ने कहा, 'सरकार सामूहिक रूप से सदन के प्रति जवाबदेह है। पीठासीन अधिकारी को निर्देश देने का अधिकार विपक्ष के पास नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को नए सांसदों को भी अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए।

चेयरमैन ने गृह मंत्री तक पहुंचाने को कहा संदेश

राज्यसभा के सभापति सी.पी। राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को निर्देश दिया कि वे विपक्ष की मांग गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाएं। वहीं, सीपीआई सांसद पी। संतोष कुमार ने सभापति के इस निर्देश को विपक्ष की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि विपक्ष लगातार गृह मंत्री से 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई पर सदन में बयान देने की मांग कर रहा था और अब उसे सकारात्मक संकेत मिला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब गृह मंत्री के जवाब का इंतजार कर रहा है।

शिंदे और उद्धव गुट में जुबानी जंग तेज, संजय राउत बोले- कोर्ट में खत्म होगा उनका खेल

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही अंतिम सुनवाई के बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने गुरुवार को दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी शिवसेना का 'खेल' कानूनी रूप से खत्म हो जाएगा।

एक्स पर एक पोस्ट में, राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) संविधान में विश्वास करती है। उन्होंने चार साल पहले पार्टी में हुए विभाजन के बाद शीर्ष अदालत में दायर की गई उनकी याचिकाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका खेल कानूनी तरीके से समाप्त हो जाएगा।' बता दें कि इस पोस्ट में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुस्कुराती हुई तस्वीर भी थी।

शिवसेना ने क्या पलटवार किया?

पलटवार करते हुए, शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी गुट अदालत के प्रतिकूल फैसले आने पर न्यायपालिका की बदनामी करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'आपका खेल तो पहले ही खत्म हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं बचा है।'

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की उन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की, जिनमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल का अपने विधायी विंग पर नियंत्रण बना हुआ है और उसके वैध निर्णय ही सर्वोपरि होने चाहिए। हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक निर्णय लेने के लिए कुछ छूट देने का भी समर्थन किया। अगर उनमें से अधिकांश राजनीतिक दल के निर्देशों से वास्तव में असहमत हों। शिंदे ने 2022 में शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे बाल ठाकरे की स्थापिकत मूल पार्टी में फूट पड़ गई। दोनों गुटों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। बाद में उनके समूह ने चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और उसका धनुष-बाण चिन्ह हासिल कर लिया।

संजय कपूर परिवार विवाद : मध्यस्थता में कितनी हुई प्रगति, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा 'ऐसा दिन न आने दें'?

नई दिल्ली, एजेंसी। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार का संपत्ति विवाद क्या अब सुलझने की राह पर है? देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया को लेकर काफी सकारात्मक संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कपूर परिवार का यह पुराना झगड़ा आपसी बातचीत से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ सकता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया बेहद संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत को पांच अगस्त की अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक मध्यस्थता के छह सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। पूर्व सीजेआई ने परिवार के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत बातचीत की है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स विशेषज्ञ की सेवाएं भी ली गई हैं। मध्यस्थ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए दो नवंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि इस पूरी मध्यस्थता प्रक्रिया का जो भी खर्च और मध्यस्थ की फीस होगी, उसका भुगतान 'आरके फैमिली ट्रस्ट' के फंड से किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने क्या चेतावनी दी?

सुनवाई के दौरान जब बातचीत विफल होने की आशंका का जिक्र आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मार्मिक और सख्त संदेश दिया। अदालत ने परिवार से कहा, 'ऐसा दिन मत आने दीजिए।' सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि वे खुले मन और खुले दिल से इस प्रक्रिया में भाग लें। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि मध्यस्थता नाकाम हुई, तो परिवार वर्षों चलने वाले कानूनी मुकदमों में उलझा रहेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया?

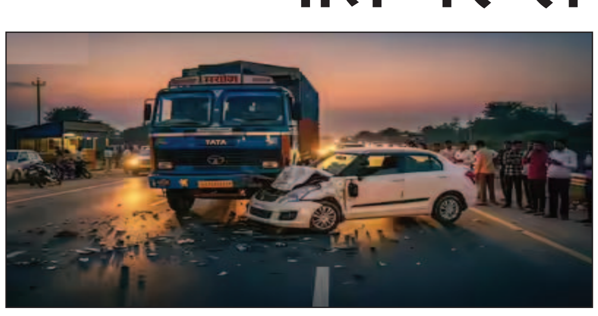

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए चालकों को ट्रैफिक नियमों और लेन अनुशासन की सही ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पर बल दिया है। संसद में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य पहलू इंसानी व्यवहार है।

इसी वजह से चालकों को लेन के नियमों और यातायात के कानूनों की वैज्ञानिक ट्रेनिंग देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ताकि दुर्घटनाओं और मौतों के आंकड़े पर लगाम लगाई जा सके।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आंकड़ों और केंद्रीय मंत्री के बयान के अनुसार, दुर्घटनाओं के पीछे इन प्रमुख कारणों को जिम्मेदार माना है:

मानव व्यवहार और ट्रेनिंग की कमी

ड्राइवरों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता और सही ट्रेनिंग का अभाव होना हादसों की सबसे बड़ी वजहों में से एक है।

गलत लेन में गाड़ी चलाना और अचानक लेन बदलना

सड़कों पर गलत लेन में वाहन चलाना या बिना किसी संकेत के अचानक लेन बदल लेना घातक हादसों का कारण बनता है।

ओवर-स्पीडिंग और लापरवाही से ड्राइविंग

पिछले साल देश में हुए अधिकांश सड़क हादसों की मुख्य वजह निर्धारित सीमा से तेज रफ्तार (ओवरस्पीड) में गाड़ी चलाना और रैश ड्राइविंग रही है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए हादसों और मौतों के आंकड़े क्या संकेत देते हैं?
राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों में कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई है:

मौतों में 4% की कमी

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2025 में 4 प्रतिशत घटकर 62,122 रह गई।

पिछले वर्षों से तुलना

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें वर्ष 2023 में 63,112 और वर्ष 2024 में 64,772 दर्ज की गई थीं।

2026 के ताजा आंकड़े

चालू वर्ष में 27 जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसों की संख्या 77,234 दर्ज की गई है।

साल 2025 में देशभर के सड़क हादसों की कुल स्थिति और भयावहता कैसी रही?

साल 2025 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़े सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं:

हादसों में 5.30% की बढ़ोतरी

वर्ष 2025 में देश भर में कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 5.30 प्रतिशत बढ़कर 5,13,563 (5.13 लाख से अधिक) हो गई।

वार्षिक और प्रति घंटे मौतों का आंकड़ा

इन 5.13 लाख से अधिक हादसों के कारण पूरे देश में कुल 1,83,382 (लगभग 1.8 लाख) लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसका मतलब है कि देश में हर घंटे औसतन 21 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई।

सड़क दुर्घटनाओं और मौतों के मामले में कौन-से राज्य सबसे आगे रहे?

वर्ष 2025 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के मामले में दो राज्यों का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा:

तमिलनाडु (सबसे ज्यादा हादसे): राज्यों की सूची में तमिलनाडु 71,387 सड़क दुर्घटनाओं के साथ हादसों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा।

उत्तर प्रदेश (सबसे ज्यादा मौतें): एक्सीडेंट से होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां 2025 में सड़क हादसों के कारण 27,550 लोगों की जान गई।

कोर्ट से बरी होने के बाद अयोध्या पहुंचे बृजभूषण, हनुमागढ़ी के दर्शन के बाद गोंडा रैली में होंगे शामिल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे। दिल्ली से हवाई मार्ग के जरिये महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका अभिनंदन किया।

एयरपोर्ट से निकलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का काफिला प्रयागराज हाईवे और लखनऊ हाईवे से होकर गुजरा। इस दौरान समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में चारपहिया वाहनों और समर्थकों की मौजूदगी के चलते कई स्थानों पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को यातायात संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़कों पर हजारों की संख्या में वाहन नजर आए, जिसके कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही।

अयोध्या पहुंचने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन-पूजन किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह गोंडा जिले के नंदिनी नगर में आयोजित 'सत्यमेव जयते' रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए।

इस मौके पर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके पिता अदालत से बरी होकर आए हैं। इसी खुशी के अवसर पर समर्थकों द्वारा उनके स्वागत और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं का प्रतीक है।

बृजभूषण शरण सिंह के अयोध्या आगमन को लेकर पूरे मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की टीमें यातायात व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रहीं, हालांकि समर्थकों की भारी भीड़ के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा।

सिकंदराराऊ में युवक का शव नीम के पेड़ से लटका मिला, खुदकुशी की वजह नहीं आई सामने

आर्यावर्त संवाददाता

हाथरस। सिकंदराराऊ कोतवाली के नगला भूड़ गांव में 6 अगस्त सुबह 8:30 बजे एक 27 वर्षीय युवक का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। युवक ने अंगौछे से गले में फंदा लगाया था। गांव के लोगों ने सत्यपाल पुत्र विजयपाल का शव गांव के बाहर एक खेत में देखा।

खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर अगसोली पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। कोतवाल शिवकुमार के अनुसार, मृतक सत्यपाल 27 वर्ष का था। वह अपने पांच भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। मृतक के पिता ने कोतवाली में आत्महत्या की तहरीर दी है।

पुलिस जांच जारी

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगसोली पुलिस चौकी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल शिवकुमार ने बताया कि युवक की आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी तक आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

टूटी पुलिया से स्कूल पहुंचना बना खतरे का सफर

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। शारदा सहायक खण्ड-16 की तुलसीपुर माइनर पर स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय आछरपुर/ऐंजर को जोड़ने वाली पुलिया जर्जर होकर फर्श पर बड़ा भाग टूट गया है। विभाग द्वारा पुलिया के दोनों किनारों पर केवल ईंटों का अस्थायी बॉर्डर बनाकर छोड़ दिया गया है, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

यह मार्ग प्रतिदिन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ-साथ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। जर्जर पुलिया से होकर गुजरना बच्चों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। पुलिया की टूटी हुई स्थिति को देखते हुए हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

बरसात के मौसम में यह खतरा और भी बढ़ जाता है, जिससे अभिभावकों एवं विद्यालय परिवार में चिंता व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिया का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने विभाग पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाते हुए स्थायी समाधान की मांग की है।

स्थानीय नागरिक तेज बहादुर तिवारी, संतोष उपाध्याय, शिवाकांत पांडेय, राकेश कुमार तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक संत कुमार एवं सहायक अध्यापक अरुण कुमार ने जिलाधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों से जनहित एवं छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जर्जर पुलिया का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने की मांग की है, ताकि स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का आवागमन सुरक्षित हो सके।

विधायक विवाद में नए ऑडियो ने मचाई हलचल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले के शहर विधायक व महिला विवाद में लगातार नए नए खुलासे हो रहे है। प्रतिदिन एक नया ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मामले में अभी तक न विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और न ही महिला जिले की मीडिया के सामने आ रही है।

बता दे कि बीते तीन दिनों से ऑडियो वीडियो बम ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। लगातार एक के बाद एक ऑडियो वायरल होने के बाद शहर विधायक की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है।वही गुरुवार को वायरल हुए ऑडियो जिले में नए विवाद को जन्म दे दिया है। वायरल ऑडियो में विधायक किसी महिला से यह कहते हुए नजर आ रहे है कि हमारे यहां सोनू, मोनू है उनसे मैने दुश्मनी इस बात को सोच कर की कि वह मेरी हत्या करा सकते है और उनकी हत्या करवाने के लिए भी हमने बात की थी तुमसे शेयर कर रहा हूं। फिर हमने सोचा कि पहले वे आक्रमण करे इसके बाद तो मैं इन्हें नेस्तनाबूद तो कर ही दूंगा।

और उनको मैने उनके घर में बैठा दिया उनकी जमीन की खरीदारी, ब्लॉक से जो करोड़ो रुपये लेते थे वह खत्म कर दिया विधायक है नहीं,तीन भट्ठे थे वह भी बंद करवा दिए अब उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। हालांकि वायरल ऑडियो पुष्टि फॉरेसिंक जांच द्वारा ही हो सकती है कि वायरल ऑडियो विधायक का ही है या स्क्रिप्टेड है। वायरल ऑडियो के संबंध में जब पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी बाहर है एक दो दिन में प्रेस वार्ता करके जवाब देंगे।

पोषण पाठशाला में आयुष्मान भारत योजना एवं स्तनपान के महत्व पर किया गया जागरूक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में गुरुवार को आयोजित पोषण पाठशाला के अंतर्गत ऑनलाइन वेबकास्ट कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर स्तनपान के महत्व एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वेबकास्ट के दौरान अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी बाल विकास एवं महिला कल्याण तथा निदेशक हर्षिता माथुर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उपनिदेशक डा0 अनुपमा साण्डिल्य तथा विषय विशेषज्ञों ने आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य, पात्रता, गोल्डन कार्ड के माध्यम से मिलने वाली कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तथा योजना का अधिकतम लाभ उठाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। साथ ही नवजात शिशुओं के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने, पहले छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने तथा स्तनपान से माँ और शिशु दोनों को होने वाले स्वास्थ्य लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डीपीओ, सीडीपीओ, मुख्य सेविकाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, आईसीडीएस के लाभार्थी, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक तथा आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। वेबकास्ट में अर्चना वर्मा (आईएएस), मुख्य कार्यकारी अधिकारी तापसिनी खेन, वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ तथा आनंद कुमार सिंह, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोषण ने अपने विचार साझा करते हुए स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। कार्यक्रम के समापन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी ,बाल विकास परियोजना अधिकारी फूल कुमार, दयाराम, राजेन्द्र प्रसाद एवं मुख्य मुख्य सेविकाओं ने कहा कि इस प्रकार की पोषण पाठशालाएं आमजन में स्वास्थ्य, पोषण एवं सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम हैं।

बदायूं में लंगूरों की तस्करी का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

बदायूं। बदायूं के कादरचौक क्षेत्र में पुलिस ने लंगूरों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को 10 लंगूरों और एक कार के साथ गिरफ्तार किया है। ये लंगूर पीलीभीत के दियोरिया जंगल से लाए गए थे और इन्हें बेचने की तैयारी थी। आरोपी ने ये लंगूर कार में ही भर रखे थे।

पुलिस को सूचना मिली थी कि कादरचौक क्षेत्र में लंगूरों की खरीद-फरोख्त चल रही है। यह काम बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए किया जा रहा था। आरोपी कादरचौक का ही रहने वाला है। वह पीलीभीत से लंगूरों को लेकर कादरचौक जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि कई लोगों ने लंगूरों की मांग की थी। प्रत्येक लंगूर 15 से 20 हजार रुपये में बिकता है। आरोपी इन्हें बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को मौके से दबोच लिया। पुलिस ने युवक से 10 लंगूर और एक कार बरामद की।

वन विभाग की कार्रवाई

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) विनीता सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही टीम को भेजा गया था। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

लंगूरों की तस्करी का कारण

बताया जा रहा है कि कादरचौक क्षेत्र में बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या है। स्थानीय लोग इस समस्या से परेशान हैं। इसी कारण लंगूरों की मांग बढ़ गई थी। तस्कर इसी मांग का फायदा उठा रहे थे।

ट्रेन में ट्रॉली बैग में लाश के टुकड़े : पैर का पंजा, पेट का कुछ हिस्सा, तेजाब डालने के कारण गल चुके थे अवशेष

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस (12621) की जनरल बोगी में बुधवार सुबह ट्रॉली बैग में मानव अवशेष से मिलने से आगरा कैंट स्टेशन पर सनसनी फैल गई। बैग से दुर्गंध उठने पर यात्री ने इसकी जानकारी दी। ट्रेन के आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने पर जीआरपी ने बैग को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बैग चेन्नई से रखे जाने की आशंका है। एक टीम जांच के लिए टीम चेन्नई भेजी जाएगी।

आगरा कैंट स्टेशन पर बुधवार सुबह करीब तीन बजे प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी से जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रॉली बैग बरामद किया। बैग में पॉलिथीन में लिपटे हुए मानव अंग मिले। यात्री ने बताया कि बैग से तेज दुर्गंध उठने के कारण बोगी में सवार अन्य यात्री भी दूसरी जनरल बोगी में सवार हो गए। सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि ट्रेन में बुलंदशहर निवासी विशाल नामक यात्री ने ग्वालियर से पहले हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दी थी। ट्रॉली बैग में मृतक का पैर का पंजा, पेट का कुछ हिस्सा मिला है। वे काले पड़ चुके थे। जो पॉलिथीन का रैपर मिला है। वह भी चेन्नई का है। आशंका है कि बैग चेन्नई से ही ट्रेन में रखा गया। किसी व्यक्ति की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए शव को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने की आशंका है। उन्होंने बताया कि जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम चेन्नई भेजी जाएगी।

ट्रेन में अंगों के मामले की जांच चेन्नई जीआरपी करेगी

तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में लाल ट्रॉली बैग से मिले मानव अवशेषों ने सनसनी फैला दी है। शुरुआती जांच में जीआरपी को आशंका है कि हत्या के बाद शव की पहचान मिटाने और उसे ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अवशेषों को बैग में भरकर ट्रेन में रखा गया।

अब पूरे मामले की कड़ी पोस्टमार्टम, डीएनए जांच और चेन्नई के सीसीटीवी फुटेज के जरिए जोड़ी जाएगी। जीआरपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कर केस चेन्नई स्थानांतरित किया जाएगा, जहां आगे की विवेचना होगी। जीआरपी के सीओ राजेश द्विवेदीने बताया कि सबसे पहले मानव अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट से मृतक की अनुमानित उम्र, मौत का समय और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे, जबकि डीएनए जांच से शव की पहचान स्पष्ट हो सकेगी। रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना देने वाले यात्री से भी पूछताछ की जाएगी।

चेन्नई स्टेशन से जुड़ रही कड़ी, जीआरपी कैंट में दर्ज की गई प्राथमिकी

यात्री ने बताया कि जब वह जनरल कोच में बैठा था, तब एक व्यक्ति लाल रंग का ट्रॉली बैग रखकर चला गया था। जीआरपी अब चेन्नई स्टेशन और कंट्रोल रूम के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी ताकि बैग लेकर आने वाले व्यक्ति, उसकी गतिविधियों और स्टेशन पर बिताए समय का पता लगाया जा सके।

स्टेशन से जुड़ने वाले मार्गों के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांची जाएगी। सीओ ने बताया कि बृहस्पतिवार को जीआरपी की संयुक्त टीम चेन्नई रवाना होगी। जीआरपी इंस्पेक्टर के अनुसार मिले अवशेषों की स्थिति देखकर आशंका है कि शव पर तेजाब डाला गया हो। इसी कारण अवशेष काले पड़ गए हैं और काफी हद तक गल चुके हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि हत्या अवैध संबंधों या किसी अन्य रंजिश के चलते की गई हो सकती है। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर उन्हें ट्रॉली बैग के जरिए अलग-अलग स्थानों तक भेजने की साजिश रची गई हो।

बांके बिहारी मंदिर का आसान होगा सफर! 15.3 किमी नई सड़क से खत्म होगा मथुरा-वृंदावन का जाम, 6922 करोड़ की हेरिटेज सिटी का क्या है पूरा प्लान?

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए हर साल करोड़ों श्रद्धालु देश-विदेश से मथुरा के वृंदावन पहुंचते हैं। लेकिन वर्षों से शहर की संकरी सड़कों और भारी ट्रैफिक जाम के कारण श्रद्धालुओं को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है। अब इस समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की महत्वाकांक्षी मथुरा हेरिटेज सिटी परियोजना को नई गति मिल गई है। करीब 6,922 करोड़ रुपये की इस परियोजना की निविदा को मंजूरी दे दी गई है। अब कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद डेवलपर का चयन किया जाएगा और निर्माण कार्य शुरू होगा।

परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बांके बिहारी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को शहर के भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचाते हुए सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15 13 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी।

यह सड़क आगे यमुना नदी पर प्रस्तावित सस्पेंशन ब्रिज से जुड़ेगी। इस नई कनेक्टिविटी के जरिए दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले श्रद्धालु बिना शहर के मुख्य ट्रैफिक में प्रवेश किए सीधे मंदिर क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे। इससे यात्रा का समय कम होगा और ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी।

मंदिर के पास नहीं जाएंगे निजी वाहन

परियोजना के तहत मंदिर क्षेत्र में निजी वाहनों के प्रवेश को सीमित किया जाएगा। श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन खड़े करने होंगे। वहां से उन्हें ई-रिक्शा और ई-बस जैसी पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवाओं के माध्यम से बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचाया जाएगा।

इस व्यवस्था से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की संख्या कम होगी। साथ ही स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं दोनों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगा।

753 एकड़ में विकसित होगी हेरिटेज सिटी

मथुरा हेरिटेज सिटी परियोजना के तहत 753 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक परिसर विकसित किया जाएगा। यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

परियोजना में थीम पार्क, ध्यान केंद्र, प्रवचन स्थल, होटल, धर्मशालाएं, पर्यटन केंद्र, रेस्टोरेंट, संग्रहालय (म्यूजियम), प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ना और मथुरा-वृंदावन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है।

6,922 करोड़ रुपये की परियोजना

पूरी परियोजना पर लगभग 6,922 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 1,954 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे, जबकि 1,310 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए गए हैं।

परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी को 5 वर्ष का मोरेटोरियम और 70 वर्ष का संचालन लाइसेंस दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण का अनुमान है कि इस परियोजना से उसे प्रतिवर्ष करीब 34 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार निविदा स्वीकृत होने के बाद अब प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही डेवलपर का चयन किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

परियोजना के लिए करीब 22 हेक्टेयर भूमि सड़क निर्माण और पार्किंग व्यवस्था के लिए अधिग्रहित की जाएगी। इसके बाद नई सड़क, पार्किंग क्षेत्र और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई पहचान

यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ। शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि मथुरा हेरिटेज सिटी परियोजना की निविदा को स्वीकृति मिल चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद डेवलपर का चयन कर परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल बांके बिहारी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान नहीं बनाएगी, बल्कि पूरे मथुरा-वृंदावन क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को नई दिशा देगी। बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक सुविधाएं और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था से आने वाले वर्षों में मथुरा देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में और अधिक सशक्त पहचान बना सकेगा।

नगर निगम का अभियान जारी : जोन-2 से 35 निराश्रित पशु पकड़े

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ ने शहर में निराश्रित पशुओं और अवैध रूप से संचालित डेयरियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत गुरुवार को जोन-2 में बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान कुल 35 निराश्रित पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर नगर निगम की टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ईटीएफ के सहयोग से अभियान सफलतापूर्वक पूरा कराया गया।नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन दल और कैटिल कैचिंग दस्ते ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अभियान के दौरान 23 गाय, 8 बछिया और 4 बछड़ों सहित कुल 35 निराश्रित पशुओं को पकड़ा गया। सभी पशुओं को नगर निगम के विशेष कैटिल कैचिंग वाहनों के माध्यम से गौशाला में सुरक्षित निरुद्ध कराया गया।कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम का विरोध करते हुए वाहनों में लादे गए पशुओं को उतारने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए ईटीएफ के जवानों ने मौके पर मोर्चा संभाला और विरोध को विफल करते हुए अभियान को बिना किसी बाधा के पूरा कराया। इसके बाद सभी पशुओं को सुरक्षित गौशाला पहुंचा दिया गया।डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि शहर में निराश्रित पशुओं की समस्या और अवैध डेयरियों के संचालन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नगर निगम का विशेष अभियान लगातार जारी है। अलग-अलग जोनों में कैटिल कैचिंग दस्ते और प्रवर्तन दल की संयुक्त टीमें नियमित रूप से कार्रवाई कर रही हैं।नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निराश्रित पशुओं एवं अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

घुमंतू विकास बोर्ड से बदलेगी विमुक्त एवं घुमंतू समाज की तस्वीर

सम्मानजनक जीवन और सरकारी योजनाओं का मिलेगा पूरा लाभः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब घुमंतू समाज को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार उन्हें सम्मानजनक जीवन, स्थायी पहचान और शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि वर्षों से उपेक्षित विमुक्त एवं घुमंतू समाज को न्याय, सम्मान और अवसर दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा।

प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के निर्णय के बाद गुरुवार को आयोजित समाज के आभार एवं अभिनंदन कार्यक्रम को

संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा रही है। बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा अथवा भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की इसी सोच का विस्तार घुमंतू विकास बोर्ड है।मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने वर्ष 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के माध्यम से उन वीर समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया था, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र भारत में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस अन्याय को समाप्त करते हुए इन समुदायों को विमुक्त जाति का सम्मान दिलाया, लेकिन लंबे समय तक उनके समुचित विकास के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इन समुदायों के लिए आयोग का गठन हुआ और उसी भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने घुमंतू विकास बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष घुमंतू समाज के सम्मेलन में बोर्ड गठन की मांग उनके समक्ष रखी गई थी और उसी समय उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अब बोर्ड के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बोर्ड में विभिन्न घुमंतू एवं विमुक्त जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचें और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने वनटांगिया, मुसहर, थारू, गौड़, चेरो, बुक्सा, कोल और सहरिया सहित अनेक वंचित समुदायों को पहली बार शासन की योजनाओं से व्यापक रूप से जोड़ा है। राशन कार्ड, भूमि के पट्टे, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान भारत कार्ड, निःशुल्क बिजली एवं गैस कनेक्शन, पेंशन योजनाओं सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन समुदायों तक पहुंचाया गया है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सभी योजनाओं से शत-प्रतिशत आच्छादित करना है।उन्होंने कहा कि सरकार ने उपेक्षित समाज के महापुरुषों और वीरांगनाओं को भी उचित सम्मान दिलाने का कार्य किया है। श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह्य की प्रतिमा, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव विजय स्मारक, जनजातीय संग्रहालय, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कॉलेज, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, ऊदा देवी पासी और झलकारी बाई के नाम पर महिला पुलिस बटालियन तथा महारानी दुर्गावती के नाम पर मेडिकल कॉलेज इसके प्रमुख उदाहरण हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय तथा श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, विद्यार्थियों, युवाओं तथा विमुक्त एवं घुमंतू समाज सहित प्रत्येक वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

गौतमपल्ली पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद किया, अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गौतमपल्ली थाना पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सर्विलांस एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी को चारबाग रेलवे स्टेशन के निकट से दबोच लिया, जबकि नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को नाबालिग की मां ने थाना गौतमपल्ली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी लगभग 16 वर्षीय पुत्री 21 जुलाई की दोपहर करीब तीन बजे से घर से लापता है। आरोप लगाया गया कि पड़ोस में रहने वाला दिनेश कुमार

उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि घर से 12 हजार रुपये नकद, आधार कार्ड, कुछ कपड़े, सोने की चेन और मंगलसूत्र भी गायब हैं।तहरीर के आधार पर थाना गौतमपल्ली में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी एवं नाबालिग की बरामदगी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने सर्विलांस सेल और अन्य तकनीकी माध्यमों की सहायता से लगातार आरोपी की तलाश की।जांच के दौरान 5 अगस्त 2026 को रात करीब 8:15 बजे पुलिस ने चारबाग रेलवे स्टेशन गेट स्थित लोको चौकी के सामने से आरोपी दिनेश कुमार (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। आरोपी मूल रूप से एमआरए विहार, थाना कैंट का निवासी है तथा वर्तमान में थाना गौतमपल्ली क्षेत्र स्थित रेलवे सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा था।पुलिस ने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जाने के बाद मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम) और 87 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 की बढ़ोतरी की गई है। मामले की विवेचना अब इन धाराओं सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की जा रही है।पुलिस ने आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मोहनलालगंज पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

लखनऊ। महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के अभियान के तहत मोहनलालगंज पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस ने पीड़िता को पहले ही सकुशल बरामद कर लिया था।पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना मोहनलालगंज में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी लगभग 16 वर्षीय पुत्री को रोशन सिंह नामक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना मोहनलालगंज में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

ठाकुरगंज में बंद पड़ी धान मिल में सांड की हत्या, तीन हिरासत में

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के न्यू हैदरगंज स्थित एक बंद पड़ी धान मिल में गौवंश (सांड) का गला काटकर हत्या किए जाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही ठाकुरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सक तथा फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने घटना के शीघ्र खुलासे के लिए विशेष टीमों का गठन करते हुए जांच तेज कर दी है। मामले में तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त 2026 को न्यू हैदरगंज स्थित एक बंद पड़ी धान मिल में गौवंश (सांड) का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल को सुरक्षित कर फोरेंसिक प्रक्रिया शुरू कराई गई। पशु चिकित्सक एवं फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य संकलित किए। इसके साथ ही घटनास्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी पूरी की गई।पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए गौवंश के शव को चिन्हित स्थान पर दफन कराया गया। घटना के संबंध में ठाकुरगंज थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।घटना के अनावरण के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों से भी विस्तृत पूछताछ की गई। अब तक की जांच और उपलब्ध वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीन व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन एवं निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आने वाले सभी तथ्यों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना में संलिप्त पाए जाने वाले सभी दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिला बदर आदेश तोड़कर लखनऊ लौटा हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, इंदिरानगर पुलिस ने दबोचा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ।इंदिरानगर थाना पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत छह माह के लिए लखनऊ जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया था, लेकिन वह आदेश की अवहेलना करते हुए अपने निवास क्षेत्र में लौट आया। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया है।पुलिस के अनुसार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ द्वारा वाद संख्या 42(25)/2026 में विशाल उर्फ बड़ा बउआ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-3 के तहत कार्रवाई करते हुए 12 जून 2026 को छह माह के लिए लखनऊ

जनपद की सीमाओं से निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया था।इसके बावजूद 5 अगस्त को इंदिरानगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर घोषित आरोपी अपने निवास क्षेत्र मुंशीपुरवा में मौजूद है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल उर्फ बड़ा बउआ (23 वर्ष) पुत्र रामलाल निवासी मुंशीपुरवा, थाना इंदिरानगर के रूप में हुई है। जांच में जिला बदर आदेश का उल्लंघन किए जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसके विरुद्ध थाना इंदिरानगर में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-10 के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश में ग्राम संगठनों का होगा विस्तार, 65,460 से बढ़ाकर 75,460 किए जाएंगे; ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं संस्थागत सशक्तिकरण को नई गति देने के उद्देश्य से प्रदेश में ग्राम संगठनों की संख्या 65,460 से बढ़ाकर 75,460 किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों का मजबूत नेटवर्क ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति है।

फर्जी क्यूआर कोड से नकली अंग्रेजी शराब बनाकर बाहर भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ पुलिस, आबकारी विभाग और दक्षिणी जोन की सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने पीजीआई क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए नकली अंग्रेजी शराब बनाने और उसकी तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 1,346 क्वार्टर अंग्रेजी शराब, फर्जी क्यूआर कोड, नकली ब्रांड लेबल और पैकिंग सामग्री बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तैयार की गई शराब को शराबबंदी वाले बिहार सहित अन्य राज्यों में असली ब्रांड के नाम पर भेजा जाता था।पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर वृंदावन योजना के सेक्टर-10सी स्थित एक किराये के मकान पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, फर्जी क्यूआर

कोड, नकली ब्रांड लेबल, ढक्कन और अन्य पैकिंग सामग्री बरामद हुई। मौके से अनिल वर्मा (36) निवासी आजाद नगर, कृष्णानगर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी विमल यादव फरार हो गया।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर नकली शराब तैयार करता था। शराब की बोतलों पर कूटरचित क्यूआर कोड और विभिन्न ब्रांडों के फर्जी लेबल लगाकर उन्हें असली के रूप में तैयार किया जाता था। इसके बाद शराब की खेप बिहार सहित अन्य राज्यों में सप्लाई की जाती थी।पुलिस ने बताया कि बरामद शराब में 612 क्वार्टर 8 पीएम प्रीमियम ब्लैक सुपीरियर व्हिस्की और 758 क्वार्टर आफ्टर डार्क ब्लू रेयर ग्रेन व्हिस्की शामिल हैं।जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से भी आबकारी अधिनियम, धोखाधड़ी और कूटरचना के कई मुकदमे दर्ज हैं तथा वह पूर्व में जेल भी जा चुका है।पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर लखनऊ पुलिस का विशेष प्रशिक्षण, संवेदनशील और समावेशी पुलिसिंग पर दिया गया जोर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके प्रति संवेदनशील एवं सम्मानजनक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ ने गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में 120 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एवं नियमावली, 2020 के प्रावधानों के साथ व्यवहारिक और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय)

अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अमित कुमावत के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। वहीं पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा ममता रानी तथा सहायक पुलिस उपायुक्त महिला अपराध शाहिदा नसरीन ने कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी निभाई।कार्यशाला में कमिश्नरेट के सभी थानों पर तैनात अतिरिक्त निरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक, वर्ष 2023 बैच के उपनिरीक्षक तथा पिंक बूथ पर नियुक्त महिला आरक्षियों सहित कुल 120 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का संचालन पहल फाउंडेशन के प्रशिक्षक यदुवेन्द्र सिंह ने किया, जिन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े कानूनी, सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी।प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एवं नियमावली, 2020 के प्रावधानों से अवगत कराना, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना तथा उनकी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और सम्मानजनक निस्तारण सुनिश्चित करना था। अधिकारियों को बताया गया कि प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को संविधान द्वारा समानता, गरिमा और स्वतंत्र जीवन का अधिकार प्राप्त है तथा पुलिस का दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को सुरक्षा, सम्मान और न्याय उपलब्ध कराए।कार्यशाला में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संवैधानिक, विधिक एवं मानवाधिकारों, शिकायतों के निस्तारण के दौरान गोपनीयता और मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने, समुदाय के साथ विश्वास आधारित संवाद स्थापित करने तथा समाज में समावेशिता और समान अवसर सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।इस दौरान प्रतिभागियों को थाना कैसरबाग में स्थापित ट्रांसजेंडर हेल्पडेस्क की कार्यप्रणाली, उद्देश्य और उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि हेल्पडेस्क के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को आवश्यक विधिक सहायता, मार्गदर्शन और पुलिस सहयोग प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा रहा है।कमिश्नरेट लखनऊ ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षित, सम्मानजनक और समान पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे संवेदीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि पुलिसकर्मियों की विधिक समझ, व्यवहारिक दक्षता और जनसेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो तथा विश्वास आधारित, समावेशी और उत्तरदायी पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

एसआरएमयू के शोधार्थी बी .डी . चौधरी ने शोध प्रबंध का सफल प्रतिरक्षण किया

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय (एसआरएमयू), बाराबंकी के प्राकृतिक विज्ञान एवं मानविकी संस्थान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के समाजशास्त्र विभाग के शोधार्थी बी.डी. चौधरी ने अपने विद्या वाचस्पति (पीएचडी) शोध प्रबंध का सफल प्रतिरक्षण एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया।शोधार्थी ने ₹उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका : वाराणसी जनपद का अध्ययन₹ विषय पर अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया। शोध में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से वाराणसी जनपद की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का व्यापक अध्ययन किया गया।अध्ययन में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, वित्तीय समावेशन, निर्णय लेने की क्षमता तथा आजीविका संवर्धन पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। शोध में यह भी बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।यह शोध कार्य समाजशास्त्र विभाग की सह आचार्य डॉ. श्वेता शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मौखिक परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर डॉ. ए.के. भारती बाह्य परीक्षक के रूप में उपस्थित रहे।

यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं

दुनिया के संभवतः किसी दूसरे देश में नैतिकता की उतनी बात नहीं होती होंगी, जितनी भारत में होती हैं। भारत ने दया, करुणा, सत्य, प्रेम, भाईचारे आदि के जितने प्रतीक गढ़े हैं, दुनिया के किसी और देश में उतने नहीं होंगे। भारत में तो एक सतयुग ही था, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र थे। लेकिन यह भी सही है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे, करुणा, दया आदि से जितनी दूरी भारत में है उतनी शायद ही कहीं और होगी। इस पर लंबी बहस हो सकती है। इसलिए उसमें जाने की जरुरत नहीं है। लेकिन दुनिया के जिन देशों में सत्य और नैतिकता आदि का ढोल रोज नहीं बताया जाता है वहां लोग ज्यादा नैतिक होते हैं। वहां लोग नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और अगर कोई अपराध किया है तो उसे भी स्वीकार करके सजा पाते हैं। भारत में कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता है और अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया व्यक्ति भी अदालत में खड़े होकर कहता है कि वह बेकसूर है और उसका पूरा परिवार और ज्यादातर मामलों में पूरी जाति उसके बचाव में खड़ी होती है।

भारत की राजनीति में भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। नैतिक जिम्मेदारी लेकर कुछ मंत्रियों आदि ने जरूर इस्तीफे दिए, जिनकी आज तक चर्चा होती है। लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया या नीतीश कुमार का जिक्र किया जाता है। यह संयोग है कि इन तीनों के इस्तीफे ट्रेन दुर्घटना को लेकर हुए थे। इनके रेल मंत्री रहते ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। यह अलग बात है कि रेल मंत्रालय में विफल होने के बाद भी इन सभी लोगों को दूसरे मंत्रालयों में अहम जिम्मेदारी मिली। लाल बहादुर शास्त्री तो बाद में प्रधानमंत्री बने। बहरहाल, भारत में गंभीर से गंभीर विफलता या आर्थिक अपराध में शामिल होने के आरोपों के बाद भी इस्तीफा कराना बड़ा मुश्किल होता है। आर्थिक अपराध के मामलों में तो अब गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी नेता इस्तीफा नहीं देते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने कमाल की मिसाल बनाई। वे कई महीने जेल में रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने थोड़ी शर्म दिखाई और गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले इस्तीफा दे दिया। अगर गिरफ्तारी की बाध्यता नहीं होती तो वे भी इस्तीफा नहीं देते।

सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि भारत में केंद्र या राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी विवाद में फंसने या अपनी कैसी भी विफलता के बाद इस्तीफा नहीं देते हैं? इसे दो पहलुओं से देख सकते हैं। एक आपराधिक मामला और दूसरा विफलता व नैतिकता का मामला। जहां तक आपराधिक मामलों में फंसने पर इस्तीफे का सवाल है तो वह इसलिए आसानी से नहीं होता है क्योंकि भारत में पहले से जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं ऐसे, सैकड़ों लोग सांसद और विधायक चुने गए हैं। सवाल है जब गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने और उनकी जानकारी सार्वजनिक होने के बावजूद जनता उनको चुन देती है तो चुने जाने के बाद किए गए किसी अपराध के लिए वे क्यों इस्तीफा देंगे? जब जनता ने उनको सांसद चुन दिया है तो वे केंद्र में मंत्री बनने के योग्य हैं और जनता ने विधायक चुना है तो वे राज्य में मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। ऐसे में उनके और जनता के बीच में नैतिकता की बात कहां से आ गई! उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि जानने के बाद भी अगर जनता ने चुना है तो वे वैसे ही किसी अन्य अपराध के मामले में भी क्यों इस्तीफा देंगे? तभी भारत में ऐसे मामलों में भी जोर जबरदस्ती ही इस्तीफा होता है। गिरफ्तार होने या गिरफ्तारी की नौबत आने या पार्टी व सरकार के प्रमुख की ओर से राजनीतिक नुकसान की आशंका देख कर दबाव डालने के बाद ही इस्तीफा होता है।

अब रही जिम्मेदारी के निर्वहन में विफलता की बात तो उसमें भी आजादी के बाद से ही यह परंपरा चलती आ रही है कि इस्तीफा जोर जबरदस्ती ही होगा। ध्यान रहे भारत में पहला हाई प्रोफाइल इस्तीफा वीके कृष्ण मेनन का हुआ था। चीन के साथ युद्ध में भारत की हार के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पर दबाव था कि वे इस्तीफा दें। लेकिन वे इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। जब जन दबाव बहुत बढ़ा तो अंत में उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि जयराम रमेश ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है, 'अ चेकर्ड ब्रिलियंसः द मेनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कृष्ण मेनन तो बहुत पहले इस्तीफा देने को तैयार थे लेकिन उन्हें रोका गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मानते थे कि चीन के साथ युद्ध में पराजय का मेनन से कोई संबंध नहीं है। फिर वे क्यों इस्तीफा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रही बातें सुन कर क्या कृष्ण मेनन के इस्तीफे की कहानी से समानता नहीं दिखती है? ध्यान रहे पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत पहले इस्तीफा देना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री को लगता था कि पेपर लीक होने से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्होंने तो पेपर लीक होने के तुरंत बाद सक्रियता दिखाई। सारे आरोपी पकड़े गए और रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा करा ली गई ताकि छात्रों का एक साल बरबाद न हो।

इतिहास में कौन प्रधानमंत्री ऐसे बदनाम हुआ

ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी से पहले और बाद में इंदिरा गांधी को गालियां मिलीं थी, पर उसमें राजनीति, गैर-कांग्रेसवाद, विचार, अनुभव सब थे।

हरिशंकर व्यास

स्वतंत्र भारत के इतिहास में कौन प्रधानमंत्री ऐसे बदनाम हुआ? इतना खलनायक हुआ? कौन गालियों का ऐसा पात्र बना? और क्यों? इसका जवाब एक प्रौढ़ महिला ने सोमवार, 20 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर दिया। मैंने उसे सोशल मीडिया पर सुना। उसने कहा, 'भारत ने बुरी सरकारें देखी हैं लेकिन ऐसी दुष्ट, क्रूर, नीच सरकार कभी नहीं! प्रौढ़ महिला हिंदू थी, पढ़ी-लिखी थी। और यह वाक्य सचमुच स्वतंत्र भारत के 14 प्रधानमंत्रियों के इतिहास में नरेंद्र मोदी के शासन की वह सच्चाई है, जो इतिहास में अमिट रहेगी। इस वाक्य को सुन मुझे भी अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के 12 प्रधानमंत्रियों के चेहरे याद हो आए। आप भी याद करें, पिछले 12 सालों में केवल प्रधानमंत्री मोदी के झूठों को, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले जुमलों को, समाज को बांटने या दुनिया में भारत को 'कॉकरोच बनाने वाली मूर्खताओं पर। और फिर बाकि प्रधानमंत्रियों पर।

मैंने 12 प्रधानमंत्रियों को पत्रकार के रूप में देखते, सुनते, समझते इनके हर समय के नैरेटिव का अनुभव लिया है। 1977 में दिल्ली के जंतर-मंतर के ही एक छोर पर कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग के बाहर खड़े हो कर मैंने इंदिरा गांधी के रायबरेली से हारने और राजनारायण के जीतने की खबर सुनी थी। जनता ने जोश भरे हुंकारे में अपनी जीत का तब जश्न मनाया था। बावजूद इसके इंदिरा गांधी को वैसी गालियां मिलती नहीं सुनीं जो इस सोमवार से जंतर-मंतर पर नौजवानों के उस सैलाब में सुनने को मिलीं है जो 35 वर्ष से नीचे की 60-65 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधि है! फिर भले लड़के हों या लड़कियां या महिलाएं!

सन् 2011-12 में जंतर-मंतर पर ही मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ नौजवानों के नारे थे, पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोई झूठा, दलाल या देश बेचने वाला रंडवा, भगोड़ा आदि (वे शब्द, जिन्हें सुनना, बोलना, लिखना मेरे लिए असंभव है) नहीं कह रहा था। मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूं। पर कहते हैं भारत के घरों में सोशल मीडिया से मोदी को दी जा रही गालियों पर मजा लिया जा रहा है। जो नौजवान 2014 में मोदी को वोट देने के लिए मरा जा रहा था, जो मोदी को भगवान और विश्वगुरू करार दे रहा था, वही आज मोदी को ऐसे-ऐसे संबोधनों से चिन्हित कर रहा है, जो संभवतया दुनिया के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को शायद ही कभी मिले हों।

हां, वैश्विक पैमाने पर भी सोचें। दुनिया में उन नेताओं को बहुत गालियां मिली हैं, जिन्होंने नरसंहार, तानाशाही का पशुपन दिखाया। पर स्टालिन, हिटलर, माओ से लेकर पोल पोट, ईदी अमीन, चिली के पिनोशे, अफगानिस्तान के मुल्ला उमर या हाल में तख्तापलट वाली बांग्लादेश की हसीना वाजिद, नेपाल के केपी शर्मा ओली आदि सभी की गालियों की दास्तां उनकी विचारधारा केंद्रित क्रूरता, नरसंहार, सत्ता की भेड़यि भूख, धर्मांधता जैसे कारणों से है। वह पूरी सत्ता या सिस्टम या सरकार के खिलाफ था। जबकि नरेंद्र मोदी का मामला अनूठा है। हिंदुओं की व्यक्तिगत भक्ति का कल्कि अवतार अब हिंदू लड़के-लड़कियों में ही उस ठग के रूप में है, जिस पर जंतर-मंतर के यूथ उबाल में यह पछतावा करता हुआ है कि हां, मैंने भी अपने मां-बाप के साथ मोदी को वोट दिया था। लेकिन मुझे घरवालों ने ही कहा- जाओ दिल्ली, जंतर-मंतर!

और जंतर-मंतर पर पुलिस-सुरक्षा बलों की पूरी फौज नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के लिए युवाओं से गालियां निकलवाते हुए है। नौजवान उस रचनात्मकता, बेलौस अंदाज में तख्तियों, मीम, पोस्टर, मोदी के फोटो के साथ जूते लटकाए हुए डायलॉग मार रहे हैं, जिसकी कल तक कल्पना नहीं थी।

यह नोट रखें कि नौजवानों के लिए न तो सोनम वांगचुक का अर्थ है और न कथित कॉकरोच पार्टी के चेहरों या पदाधिकारियों का। नई पीढ़ी अनुभवों के गुस्से में, अपनी दशा, अपने साथ झूठ, धोखे, फरेब-ठगी से घायल है। सभी केवल और केवल मोदी पर केंद्रीत है।

ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी से पहले और बाद में इंदिरा गांधी को गालियां मिलीं थी, पर उसमें राजनीति, गैर-कांग्रेसवाद, विचार, अनुभव सब थे। 'गली-गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है जैसे नारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को बिल्ले बांटते हुए बताए थे। अब बच्चे खुद ही गढ़ रहे हैं।

सभी के निशाने में केवल एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। बच्चे, लड़के-लड़कियां, युवा के दिल-दिमाग में मोदी एकमेव हैं। अमित शाह और चुनाव आयोग के लिए संभव है कि वे जंतर-मंतर के कॉकरोचों की भीड़ से फोटो स्कैन कर इन सभी के नाम वोटर लिस्ट से काट दें। मतलब मोदी-शाह गालियों के बावजूद यूपी आदि के चुनाव जीतते जाएं। लेकिन अब वह जैविक नौजवान जोश कभी नहीं लौटेगा, जिसने कभी कभी घर-घर हर-हर मोदी बनाया था। चुनाव प्रक्रिया में कितनी ही तरह की ठगी रची जाए, राज चलता जाए, पर समय के साथ मोदी की स्मृति की गालियां भी बढ़ती जानी हैं।

इसलिए क्योंकि आगे वाले दिनों में बुरे दिनों के अनुभव अनिवार्यतः जुड़ने है। आगे मोदी सरकार में दैनंदिन जीवन की बदहाली और दर्ज होनी है। संभव ही नहीं है जो अच्छे दिन, छप्पन इंची छाती, विश्वगुरु, आत्मनिर्भर भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई मुक्त भारत, सबका साथ-सबका विकास, हर हाथ को काम या शिक्षा-चिकित्सा में मोदी से कुछ भी पॉजिटिव बने। अपना अब वे जितना प्रोपेगेंडा रचेंगें उतने ही नेगेटिव मोदी बनेंगे। वह भी सोशल मीडिया के भोकाल वाली युवा जुबानी।

व्यंग्य

डोपिंग का घुन

वाडा और एआईयू जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों से भारत में इस समस्या के लगातार गहराने की पुष्टि हुई है, लेकिन खेल संस्थाओं या सरकार ने इस दिशा में कोई सख्त एवं प्रभावी पहल नहीं की है।

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ही दिन जुडो खिलाड़ी अरुण कुमार को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण इस आयोजन से बाहर कर दिया गया। इसके पहले कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों को भी इसी टेस्ट में फेल होने के कारण इन खेलों में भाग लेने से रोक दिया गया था। खेलों की दुनिया में भारत के लिए यह नई शर्मनाक स्थिति है। हालिया वर्षों से विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी- वाडा- की रिपोर्ट में भारत दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, और कुश्ती में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरअसल, कई एथलीटों के डोप टेस्ट में विफल होने के कारण ग्लासगो गेम्स में भारत के वेटलिफ्टिंग कोटा में कटौती कर दी गई।

हाल में डोपिंग के मामले क्रिकेट, फुटबॉल और बॉक्सिंग जैसे खेलों में भी सामने आए हैं। नतीजतन, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (एआईयू) ने भारत को उच्च-जोखिम वाली श्रेणी में डाल दिया है। एआईयू के इस निर्णय से खेल जगत में भारत की साख कमजोर हुई है। इसका नतीजा यह होगा कि अब अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलीटों को अधिक सख्त और अतिरिक्त परीक्षणों से गुजरना होगा। बड़े खेल आयोजनों से पहले भारतीय खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल होते रहे, तो अंतरराष्ट्रीय खेल संघ भारत के कोटा (प्रतिनिधित्व के लिए खिलाड़ियों की संख्या) में कटौती कर सकते हैं।

यह आशंका भी है कि अन्य देश और प्रायोजक भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों को संदेह की नजर से देखने लगें। मगर इन अंदेशों से भारतीय खेल प्रशासक बेपरवाह नजर आते हैं। वाडा और एआईयू जैसी संस्थाओं की रिपोर्टों से देश में इस समस्या के लगातार गहराने की पुष्टि होती रही है, लेकिन खेल संस्थाओं या भारत सरकार ने इस दिशा में कोई सख्त एवं प्रभावी पहल नहीं की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय भारत सरकार ने ओलिंपिक में अधिक मेडल जीतने की कथित योजनाओं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने जैसी महत्त्वाकांक्षी बातों में देशवासियों को उलझाए रखा है, उसी समय खेल की जड़ों को डोपिंग का घुन कुतरता जा रहा है।

ब्लॉग

अंत में अब 'कॉकरोच' का लेबल!

हरिशंकर व्यास

सन् 2026 की 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच भारत में वह हुआ, जिसकी दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश ने कल्पना नहीं की। दुनिया के अखबारों, टीवी चैनलों और डिजिटल मंचों पर भारत बतौर 'कॉकरोच की पहचान के साथ उभरा। कभी 'सांप-संपेरों के हिंदुस्तान की इमेज थी। पर 1947 में स्वतंत्रता के बाद के दशकों में लोकतंत्र, भारत-निर्माण, आईटी, उभरती आर्थिकी, परमाणु ताकत, आईआईटी-आईआईएम सहित शिक्षा की बेहतरी तथा विशाल जनसंख्या के बाजार के नाते भारत प्रतिष्ठित हुआ। वह सब अब हाशिए में है और अब भारत 'कॉकरोच है। भारत में मनुष्य, नवजात पीढ़ी 'कॉकरोच है, जिस पर लाठियां, पैलेट गन की गोलियां बरसी। यह वैश्विक अजूबा है और तभी दुनिया के हर कोने में अखबारों के पहले पेज पर, बैनर हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज की तरह छपा। सवाल है, कौन दोषी, किसने कॉकरोच भारत बनाया है? क्या संघ परिवार और उसके प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं? इसलिए 'कॉकरोच फर्जी हिंदू राष्ट्र, फर्जी अमृतकाल का वह कलंक है, जिससे भले मोदी सरकार और भक्त हिंदू शर्मिंदा न हों, लेकिन विश्व मानव समाज अवश्य 145 करोड़ लोगों के भारत को जुगुप्सा, वितृष्णा से देख, समझ रहा है।

सोचें, इक्कीसवीं सदी में दुनिया में आगे भारत अब क्या इमेज लिए है? एक ऐसा देश, जो स्वयं को 'विश्वगुरु, 'लोकतंत्र की जननी, 'विकसित भारत और 'विश्वबंधु बताता है, वहां 'कॉकरोच है, 'कॉकरोच राजनीति है, 'कॉकरोच आर्थिकी है, आदि-आदि। मोदी ने, अमित शाह ने पहले भारत के नागरिकों के आगे अनागरिक होने की तलवार लटकाई। पश्चिम बंगाल के लाखों दस्तावेज़युक्त वैध मतदाताओं को अनागरिक बनाकर उन्हें मताधिकार से बाहर किया। इसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने अपराध नहीं माना। फिर पूरे भारत के नागरिकों में ही मनुष्य को सर्वोच्च अदालत से 'कॉकरोच परजीवी होने की तख्ती मिली!

बावजूद इसके हिंदू राष्ट्र के भक्त हिंदुओं को शर्म नहीं आई, न ग्लानि हुई। इन हिंदुओं के हिंदू होने के डीएनए की सचमुच जांच होनी चाहिए। ये कौन से, क्या हिंदू हैं, इसका जवाब सनातन धर्म का शायद ही कोई ग्रंथ दे पाए। मैं हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं और मुझे इतना सामान्य ज्ञान है कि सनातन धर्म में मानव जन्म को परम प्राप्ति कहा गया है। जन्म-जन्मांतर के विश्वासी हम सनातनियों का मूल सूत्र है कि मनुष्य, ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है। भगवान ने (श्रीमद्भागवत पुराण 11.9.29) अपनी मायाशक्ति से वृक्ष, सरीसृप (सांप आदि), पशु, पक्षी, मच्छर, मछलियां आदि अनेक योनियां बनाईं। परंतु उन्हें तब तक संतोष नहीं हुआ, जब तक उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना नहीं की। और ईश्वर स्वयं मनुष्य शरीर में ब्रह्म (ईश्वर) को जानने और देखने की बुद्धि देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसा ही आदि शंकराचार्य का दिया सूत्र (विवेकचूड़ामणि, श्लोक 2) है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। मनुष्य होने के बाद पुरुषत्व, फिर वैदिक धर्म का मार्ग जानना, फिर विद्वान होना, और उसके बाद आत्मा-अनात्मा का विवेक प्राप्त करके ब्रह्म में स्थित होना, यह सब सौ करोड़ जन्मों के पुण्यों के बिना संभव नहीं है।

तभी, जब मैंने चीफ जस्टिस का 'कॉकरोच वाला वाक्य और बाद में उनकी सफाई सुनी, तो बतौर ब्राह्मण मुझे ग्लानि हुई कि हम आज के ब्राह्मण कैसे हैं! कितने अविवेकी, बुद्धिहीन हो गए हैं! देश की सर्वोच्च अदालत का चीफ जस्टिस मनुष्य पर 'कॉकरोच का लेबल चस्पां कर रहा है! जाहिर है, चीफ जस्टिस का विवेक भी नरेंद्र मोदी नाम के कथित कल्कि अवतार के समय में ब्राह्मणों के विवेक, पुरुषत्व, ज्ञान और बुद्धि, सभी के पतन की बानगी है। सोचें, गंभीरता से सोचें कि चीफ जस्टिस के साथी जजों से लेकर सर्वज्ञ, अजैविक भगवान नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के मंत्रियों, संघ और हिंदू साधु-संतों में किसी के भीतर भी इस शब्द को बदलवाने, शब्द-वापसी, पछतावा, शर्म या खेद प्रकट कराने की बुद्धि या हिम्मत नहीं आई। जबकि आदि शंकराचार्य ने मनुष्य के पुरुषत्व (सत्यनिष्ठ निर्भयता), विद्वत्ता तथा आत्मा-अनात्मा के विवेक के माध्यम से ब्रह्म में स्थित होने तक की क्षमता में हर मनुष्य से मानवीय व्यवहार और संवेदना की अपेक्षा की है।

जार्ज ऑरवेल का एक महान उपन्यास है, 'एनिमल फार्म। इसमें मनुष्य की प्रवृत्तियों की वास्तविकताओं पर पशुओं के जंगल राज की कहानी है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे सुअर सत्ता हथिया लेते हैं और समानता के नाम पर नया अत्याचार खड़ा कर देते हैं। लेकिन ऑरवेल भी यह नहीं सोच सकते थे कि किसी लोकतंत्र में, मानव समाज में मनुष्यों की तुलना कीड़े-मकोड़ों, कॉकरोचों से होगी और शासन फिर इन कॉकरोचों को आंसू गैस के गोलों से खत्म करने के आदेश देगा।

इसलिए मसला गहरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक को (भले वह परजीवी हो) 'कॉकरोच करार देना नए भारत के वर्तमान और भविष्य की दशा-दिशा है। पिछले बारह वर्षों से सरकार ने नौजवानों (बहुसंख्य आबादी को ही) अवसरों से वंचित किया है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। लोगों को सही शिक्षा, सही चिकित्सा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय उन्हे पैसा बांटकर, झांसा देकर परजीवी और आश्रित बनाया है। बेमतलब की डिग्रियां बांटी जा रही हैं। परीक्षाओं के नाम पर लूट है, झांसा है। स्वाभाविक है कि सामान्य छात्र हो या वकीलों तथा स्नातक-स्नातकोत्तर डिग्रियां लिए नौजवान, बेगारी का जीवन जीते हुए है। यूथ (जैसे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील थे) भटकते-भटकते अन्याय और अवसरों की गुहार लगाता है, तो उसे क्या तमगा मिलता है? 'कॉकरोच (परजीवी)! और फिर दुनिया के आगे 'कॉकरोच भारत!

याद करें पिछले बारह वर्षों के अनुभवों पर। मोदी सरकार ने लोगों को (उनकी देखा-देखी बाकी सरकारों और पूरी राजनीति ने भी) लाभार्थी, खैराती और परजीवी बनाने का मिशन चला रखा है, और फिर उनकी नागरिकता पर भी सवाल खड़ा किया। अंत में अब 'कॉकरोच (क्योंकि परजीवी) का लेबल! बारह वर्षों में न नागरिकों को पुरुषार्थी और स्वाभिमानी बनाया, न ही उन्हें समान अवसर दिए, मगर उन्हें कॉकरोच बना दिया!

पता है, दुनिया में 'कॉकरोच शब्द नरसंहार का संदर्भ लिए हुए है। अफ्रीका के देश रवांडा में तुत्सी समुदाय को 'कॉकरोच कहा गया था। फिर उन पर कहर बरपा और वह शब्द नरसंहार की राजनीति का भी प्रतीक बना। संयुक्त राष्ट्र तथा मानवाधिकार अध्ययनों में ऐसी भाषा को अमानवीकरण (अर्थात मनुष्य को मनुष्य न मानने वाली भाषा) के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे ही हिटलर ने यहूदियों को मारने के लिए उन्हें 'चूहा कहा था। और गुजरे सप्ताह हिंदू लड़के-लड़कियों पर जब पैलेट गन से छर्रे मारे गए, तभी भक्त चेहरों के ये वाक्य भी छपे थे कि देश से 'कॉकरोचों को खत्म करने का स्थायी इंतजाम हो। या 'कॉकरोचों के पीछे 'विदेशी ताकतें, 'खालिस्तानी संगठन, 'बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी की ताकतें, 'पाकिस्तान समर्थित ताकतें और 'सोरोस फाउंडेशन हैं!

क्या यह रवांडा के पागलों जैसी भाषा नहीं है? गंवार हिंदू राष्ट्रवादियों को इतनी भी समझ नहीं है कि राष्ट्रों की प्रतिष्ठा अर्थव्यवस्था, सेना या चुनावों से नहीं बनती; बल्कि प्राथमिक कसौटी यह है कि वहां की सरकार अपने सामान्य नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करती है? दक्षिण अफ्रीका वर्षों तक रंगभेद से कलंकित रहा। ऐसे ही सैन्य दमन से म्यांमार की पहचान मानवता का कलंक थी और है। चीन और रूस भले महाशक्ति हों, लेकिन ये मनुष्यों पर तानाशाही की स्थायी पहचान वाले देश हैं।

सोचें, नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए विश्व की राजधानियों में जाकर क्या-क्या तमाशे नहीं किए? जी-20 सम्मेलन से लेकर 'भारत मंडपम, योग दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मेलनों आदि पर बेहिसाब पैसा उड़ेला। बारह वर्षों से सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगंडा मोड में है। लेकिन भारत की सरकार को, उसके नेता को यह पता नहीं है कि विज्ञापनों, भाषणों, मीडिया और प्रोपेगंडा से इमेज नहीं बनती। राष्ट्र स्तर पर वह उस सार्वजनिक व्यवहार से बनती है, जिसे दुनिया के अलग-अलग पैमाने और इंडेक्स समय-समय पर मानव समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। पर जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, जो सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग अपने नागरिकों को स्वयं 'कॉकरोच का चरित्र प्रमाणपत्र दे, उस राष्ट्र का क्या चरित्र प्रमाणपत्र होगा? क्या 'कॉकरोच नहीं? हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या आदिवासी, उच्च वर्ग हो या मध्यवर्ग, सभी को मोदी सरकार ने परजीवी बनाकर, उन्हें संदिग्ध नागरिक, अवैध मान कतार में खड़ा कर दिया है, तो उस देश को क्या कहेंगे? अब क्या है मां भारती? मोदी-शाह संसद में 'वंदे मातरम् का गान अनिवार्य बना रहे हैं, जबकि मां भारती का क्या अर्थ बना दिया है? 'कॉकरोचों की पालक, पोषक और जननी! और 'कॉकरोच उर्फ मासूम लड़के-लड़कियां पैलेट गन से निशाना बनाने लायक!

कोई न माने, लेकिन भारत राष्ट्र का साधारण मनुष्य आज 'कॉकरोच का चरित्र प्रमाणपत्र लिए हुए है और वही भारत राष्ट्र का भी चरित्र प्रमाणपत्र है। इसे न कल्कि अवतार नरेंद्र मोदी समझते हैं, न कलियुगी चाणक्य अमित शाह, न चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न चुनाव आयोग में बैठे कथित ज्ञानी ज्ञानेश कुमार और न संघ परिवार के कथित परम पूजनीय मुखिया मोहन भागवत! क्या यही संघ के सौ वर्षों का प्रारब्ध नहीं है?

कोटा-देहरादून के बाद प्रयागराज

राहुल का कार्यक्रम रद्द होने पर भड़की कांग्रेस, अजय राय बोले- ये हर हाल में होकर रहेगा

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम पर सियासत गरमा गई है। कार्यक्रम की अनुमति निरस्त होने पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चाहे जितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, 8 अगस्त को प्रयागराज की पावन धरती पर राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम हर हाल में आयोजित होगा। अजय राय ने कहा कि सरकार के दबाव में अनुमति निरस्त की गई है।

अजय राय ने कहा, पी ट्रस्ट ने ही छात्रों से संवाद के लिए राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति दी थी। 30 जुलाई को मंजूरी मिली थी। उस समय ट्रस्ट की ओर से किसी तरह की कोई अन्य बात नहीं कही गई थी। सब कुछ ठीक था तभी ट्रस्ट ने अनुमति दी थी।

अजय राय ने कहा है कि इसके पहले राजस्थान के कोटा में बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को निरस्त था। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को दबाव डालकर निरस्त कराया था। अजय राय ने कहा कि कोटा और देहरादून दोनों जगह सरकारों को बाद में अनुमति देनी पड़ी और अब छात्रों के दबाव में प्रयागराज में भी सरकार को अनुमति देनी पड़ेगी।

राहुल गांधी हर हाल में जाएंगे

अजय राय ने कहा कि प्रयागराज की धरती बहादुरों और शहीदों की धरती है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हजारों हजार छात्र अपना भविष्य तलाश में आते हैं। संगम नगरी जाकर बच्चे आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी हरहाल में 8 अगस्त को प्रयागराज जाएंगे और बच्चों से संवाद भी करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार व प्रशासन राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए दूसरे विकल्प मुहैया कराए।

प्रियंका ने क्या कहा?

वहीं प्रयागराज में कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति निरस्त होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "पता नहीं वे किस बात से डर रहे हैं।"

विधि शिक्षा में करियर बनाने की संभावनायें

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान में बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिवस विद्यार्थियों को विधि शिक्षा में करियर की संभावनाओं, व्यक्तित्व विकास तथा मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से अवगत कराया गया। प्रथम सत्र में विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के समन्वयक प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि विधि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका, प्रशासन, कॉर्पोरेट क्षेत्र और समाज सेवा में नेतृत्व स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से अध्ययन के साथ-साथ इंटर्नशिप, मूट कोर्ट, विधिक शोध, ड्राफ्टिंग तथा प्रभावी संचार कौशल विकसित करने का आह्वान किया, जिससे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और करियर के बेहतर अवसर प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने न्यायिक सेवा, अधिवक्ता के रूप में वकालत, लोक अभियोजक, सरकारी विधि अधिकारी, कॉर्पोरेट लॉ, बैंक एवं सार्वजनिक उपक्रमों में विधि अधिकारी, राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं, विधिक शोध एवं शिक्षण, लीगल कंसल्टेंसी, आर्बिट्रेशन एवं मेडिएशन, कंपनी सेक्रेटरी, भारतीय सेना की जेएजी (जज एडवोकेट जनरल) शाखा तथा भारत और विदेश की प्रतिष्ठित लॉ फर्मों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करियर के अवसरों की जानकारी दी।

अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान की मौत, सड़क हादसे में गई जान

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, आबान अहमद अपने भाई से मिलने प्रयागराज से झांसी जेल जा रहा था। तभी यह हादसा हो गया। झांसी के पूंछ थाना इलाके में हाईवे पर उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में आबान अहमद समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा। बता दें कि अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

नींद आने की वजह से हुआ हादसा!

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुबह-सुबह का वक्त था, जब आबान की कार डिवाइडर से टकराई। नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में अतीक के छोटे बेटे आबान की मौत हो गई। वह अपने बड़े भाई जो झांसी के जेल में बंद है, उससे मिलने जा रहा था। फिलहाल झांसी जिला प्रशासन इस मामले को अलग-अलग एंगल से देख रही है। वहीं, झांसी के SSP ने बताया कि मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान की मौत तेज रफ़्तार कार के डिवाइडर से टकराने के बाद हो गई। इस हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई।

अतीक के पांच बेटे थे, अब कितने बचे?

अतीक अहमद और उसके परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो मारे जा चुके हैं, जेल में हैं या फिर फरार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आज अतीक का पूरा परिवार किस हाल में है? अतीक के पांच बेटे थे, अब कितने बचे? अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के पांच बेटे थे। एक समय प्रयागराज में सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले अतीक अहमद का परिवार अब पूरी तरह बिखर चुका है। दो बेटे जेल में हैं, दो बेटों की मौत हो चुकी है, पत्नी और अन्य महिला रिश्तेदार फरार हैं।

गढ़ढे में डूबने से दो बालकों की मौत

जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र के गारोपुर गांव में बुधवार शाम समरसेबुल पंप लगाने के लिए खोदे गए पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गारोपुर निवासी अच्छेलाल उर्फ पप्पू गौतम ने समरसेबुल पंप लगाने के लिए मंगलवार को बोरिंग कराई थी। बोरिंग के लिए खोदा गया गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था, जिसमें पानी भर गया था। गांव के छह वर्षीय शिवा बिंद पुत्र वीरेंद्र बिंद तथा वर्षीय आरव बिंद पुत्र अनिल बिंद खेलते हुए उसी रास्ते से गुजर रहे थे, इसी दौरान दोनों बच्चे पानी भरे गड्ढे में गिर गए। काफी देर तक दोनों बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। घर से लगभग 100 मीटर दूर स्थित गड्ढे में खोजबीन के दौरान दोनों बच्चे पानी और दलदल में फंसे मिले। ग्रामीण तत्काल उन्हें उपचार के लिए कटवार बाजार ले गए, जहां से गंभीर हालत में सुरियावां के एक अस्पताल पहुंचाया गया।

'लड़कियों को तड़पता देख अच्छा लगता है...', कांस्टेबल ने श्मशान घाट में 10 साल की मासूम से की दरिंदगी, फिर मार डाला

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खाकी को शर्मसार करने वाली एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस विभाग में डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव ने 10 साल की एक मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया और फिर बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। जेल में बंद आरोपी सिपाही को पुलिस ने 10 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की, तो उसने हैवानियत की ऐसी दास्तान सुनाई जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों की भी रूह कांप गई।

आरोपी सिपाही अभिषेक यादव ने पूछताछ में कबूला कि उसने पहले से ही तय कर लिया था कि उसे किसी लड़की को शिकार बनाना है। वह पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी क्वार्टर से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू साथ लेकर निकला था। 28 जुलाई की रात करीब 10:00 बजे उसने गोरखपुर जिला अस्पताल से

10 साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। सिपाही बच्ची को लेकर सीधे श्मशान घाट पहुंचा, जहां उसने मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में सिपाही ने बताया कि बच्ची लगभग 45 मिनट तक दर्द से तड़पती और चीखती-चिल्लाती रही।

सिपाही ने पुलिस के सामने कबूला कि वह पुलिस क्वार्टर में अकेला रहता है क्योंकि 1 साल से पत्नी और बच्चे अलग रहते हैं। उसे महिलाओं-लड़कियों को तड़पते देखना अच्छा लगता है। जब बच्ची के चिल्लाने पर उसे डर लगा कि कोई आ न जाए, तो उसने गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी। पहचान मिटाने की नीयत से सिपाही ने चाकू से मासूम के चेहरे और शरीर के अंगों पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें क्षत-विक्षत कर दिया। इसके बाद उसने बच्ची के लोअर से डोरी निकालकर उसके हाथ पीछे बांध दिए और शव को चिउटहा पुल से नीचे फेंक दिया।

पुलिस रिमांड, सीन री-क्रिएशन और आला-ए-कत्ल बरामद

4 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को जेल से 10 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लिया। पुलिस टीम आरोपी को जिला अस्पताल, श्मशान घाट और चिउटहा पुल ले गई, जहां घटना का री-क्रिएशन कराया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी और गवाहों के बयानों का मिलान कर मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी ताकि दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।

बारिश से जल जमाव, आवागमन में बाधा

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिले में बुधवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने गुरुवार दोपहर तक जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है। नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाली नालियां और नाले पूरी तरह भर गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया। विद्युत विभाग और जिला प्रशासन ने बारिश से पहले बिजली के खंभों को पॉलीथीन या प्लास्टिक पाइप से ढकने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद, नगर के कई खंभे अभी भी खुले पड़े हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। पूर्व में ऐसे नंगे खंभों के कारण तीन लोगों की जान जा चुकी है।जलभराव के कारण सड़कों के गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे चार पहिया और दो पहिया वाहन फंस रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। मूसलाधार बारिश के मद्देनजर, जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. के निर्देश पर गुरुवार को जिले के सभी परिषदीय (बेसिक) विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया। बरसठी विकास खंड में गुरुवार सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बरसठी जाने वाला मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया। बुधवार रात से हो रही बारिश के कारण रेलवे फाटक के पास एक यूकेलिप्टस का पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे अस्पताल का संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। इससे मरीजों और एम्बुलेंस को आवागमन में परेशानी हुई। मीरगंज क्षेत्र के रामपुरखुर्द गांव की दलित बस्ती का संपर्क मार्ग भी जलभराव के कारण पूरी तरह डूब गया है। रास्ते पर घुटनों तक पानी भर जाने से ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है।

प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा, एक ही झटके में खत्म हो गया पूरा परिवार, माता-पिता, बेटा-बहू समेत छह की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के चिलबिला कोतवाली के महुली मंडी इलाके में बड़ा हादसा हो गया। बुधवार की देर रात करीब ढाई तीन बजे एक जर्जर मकान धराशायी हो जाने से उसमें दबकर एक ही परिवार के छह लोगों की जान चली गई। यह मकान 100 साल पुराना बताया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए हर संभव मदद की घोषणा की है।

जिन लोगों की मलबे में दबकर जान गई है, उसमें महादेव (2) पुत्र अमन श्रीवास्तव, रीता श्रीवास्तव (42) पत्नी प्रमोद श्रीवास्तव, प्रमोद श्रीवास्तव (45) पुत्र कामता प्रसाद श्रीवास्तव, माधुरी (24) पत्नी अमन श्रीवास्तव, बाबू (छह माह) पुत्र अमन श्रीवास्तव शामिल हैं। मलबे में कुल सात लोग दबे थे। जिसमें छह की मौत हो गई है।

100 पुराना था मकान

शहर के महुली वार्ड के रहने वाले प्रमोद श्रीवास्तव पुत्र कामता प्रसाद श्रीवास्तव बुधवार की रात भोजन करने के बाद परिवार के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। रात में बारिश हो रही थी। करीब दो बजे के आसपास मकान की छत भरभराकर गिर पड़ी। सभी मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम व स्थानीय लोगों ने मलबे से प्रमोद श्रीवास्तव (45), पत्नी रीता श्रीवास्तव (42) नितिन (24) पुत्र प्रमोद श्रीवास्तव , बहू माधुरी(24)पत्नी अमन श्रीवास्तव, पोते माधव (2) और बाबू (6 माह) बाहर निकाला।

आनंद फानन में सभी मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम घटना की जांच कर रही है। सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में परिवार का एक सदस्य सुरक्षित बचा है। पटना की जांच की जा रही है।

संक्षेप

पड़ोसियों ने माँ बेटी को पीटा

जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के राजेपुर मतुला गांव निवासी एक माँ-बेटी को बुधवार की शाम को पड़ोसियों ने पुराने विवाद को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया।पीड़ति ने गुरुवार को घटना की तहरीर पुलिस को दिया।उक्त गांव निवासी मकोई देवी पत्नी मेहीलाल सोनकर द्वारा एक विवादित जमीन पर पतरा ईंट रखने को लेकर पड़ोसी छबु व दुलार पुत्र बैजू सोनकर व सोहित पुत्र बबई सोनकर ने पहले गालियां देने लगे।जब मना किया तो तीनों ने उसे तथा उसकी माँ को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया।थानाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है।तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंखे में करंट से मासूम बच्ची की मौत

जौनपुर। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र पतहना गांव में पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसी बच्ची गुरुवार को जिला अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना से परिजन में कोहराम मच गया। उक्त गांव निवासी सुरेंद्र गौतम की पांच वर्षीया पुत्री सान्वी गौतम पंखे में उतरे करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन और पड़ोसी बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर चिकित्सकों ने देखने के बाद उसे मृतक घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद भी परिजन बगल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए वहां पर भी चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

किषोरी को अपहृत करने का आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर। शहर कोतवाली पुलिस ने दो वर्ष पूर्व अपहरण हुई किषोरी को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के तूतीपुर मोहल्ले से दो वर्ष पूर्व एक लड़की को शिवापार गांव थाना लाइन बाजार निवासी हाल पता सिपाह दशरथ सोनकर उसे बहका फुसलाकर भगा ले गया था। जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में उसी समय दर्ज कराई गई थी। विवेचना कर रही पुलिस को जानकारी मिली कि लड़की आरोपी के साथ इस समय सिपाह में मौजूद है। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी दशरथ सोनकर को गिरफ्तार कर उसके पास से अपहरण हुई लड़की को बरामद कर लिया, जबकि यह लड़की अब 19 वर्ष की होने के कारण पूरी तरह से बालिग हो चुकी है। पुलिस ने अपहरण हुई लड़की को जिला महिला अस्पताल भेज कर उसका चिकित्सकिय प्रशिक्षण कराया।

मड़हा में लगी आग से दुधारू गाय मरी

जौनपुर।गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर द्वितीय गांव में बुधवार की रात लगभग एक बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मड़हा में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में मड़हे के भीतर बंधी एक दुधारू गाय की जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरी गाय गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़ति पशुपालक ने घटना की तहरीर थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।उक्त गांव निवासी राहुल पाल का मड़हा स्थित है, जिसमें उनकी मवेशी बंधी हुई थीं। रात करीब एक बजे अचानक मड़हे से लपटें उठने लगीं। जब तक ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया।

गंदगी से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्षन

जौनपुर। मड़ियाहूं तहसील क्षेत्र के रामपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में जलभराव और गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद कुमार जायसवाल और सभासद मुकेश मिश्रा पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, नाली की सफाई न होने के कारण मुख्य मार्ग पर पानी जमा हो गया है। इससे आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है, और कई बार लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। बगल में नाली होने के बावजूद, जाम होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। बताया कि क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से बिजली गुल है।

उर्स में नहीं बनेगी बिरयानी, सावन में हिंदू भाइयों के लिए दरगाह का फैसला... बनी मिसाल

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। बरेली में सुन्नी-बरेलवी मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र दरगाह आला हजरत से इस बार सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश देने वाला अहम फैसला सामने आया है। 108वें उर्स-ए-रजवी के दौरान लगने वाले लंगरों में इस बार मांसाहारी भोजन नहीं बनाया जाएगा। दरगाह प्रमुख मौलाना सुब्हान रजा खान (सुब्हानी मियां) ने सभी लंगर कमेटियों से अपील की है कि वे केवल सात्विक और शाकाहारी भोजन ही श्रद्धालुओं को परोसें। उनका कहना है कि इस समय हिंदुओं का सावन का पवित्र महीना चल रहा है। पूरे बरेली में शिवभक्ति का माहौल है ऐसे में सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है

दरगाह प्रबंधन का मानना है कि उर्स का मकसद मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का संदेश देना है। इसलिए इस बार लंगरों में बिरयानी या किसी भी तरह के मांसाहारी पकवान की जगह पूरी, सब्जी, खिचड़ी, चावल, दाल और अन्य शाकाहारी व्यंजन तैयार किए जाएंगे। इस फैसले को शहर में गंगा-जमुनी तहजीब की एक अच्छी मिसाल माना जा रहा है।

सावन के चलते बदला गया उर्स का कार्यक्रम

6 अगस्त को परचम कुशाई के साथ उर्स-ए-रजवी की शुरुआत होगी। पहले कुल शरीफ 9 अगस्त को प्रस्तावित था, लेकिन सावन के अंतिम सोमवार को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया गया। दरगाह प्रबंधन का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान शहर का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे, इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

इंतजामिया कमेटी के सदस्य नासिर कुरैशी ने बताया कि दरगाह प्रमुख ने सभी लंगर कमेटियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं भी मांसाहारी लंगर न लगाया जाए। सभी स्थानों पर सिर्फ शाकाहारी भोजन ही वितरित किया जाए। ताकि हर धर्म और समुदाय के लोग बिना किसी संकोच के लंगर में शामिल हो सकें।

हर साल सैकड़ों लंगर लगते हैं, इस बार होगी नई शुरुआत

उर्स-ए-रजवी के दौरान इस्लामिया मैदान, मथुरापुर स्थित मदरसा जामियतुर्रजा समेत शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा रजाकारों और सामाजिक संगठनों की ओर से सैकड़ों लंगर लगाए जाते हैं। अब तक अधिकतर लंगरों में बिरयानी और अन्य मांसाहारी भोजन बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार परंपरा में बदलाव देखने को मिलेगा।

दरगाह प्रमुख मौलाना सुब्हानी मियां ने कहा- सावन के महीने में सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उर्स का संदेश प्रेम, अमन और इंसानियत का है। इसलिए सभी लंगर कमेटियां ऐसा भोजन तैयार करें, जिससे समाज में भाईचारा और आपसी विश्वास और मजबूत हो यही उर्स-ए-रजवी की असली पहचान भी है।

किन्नरों के दो गुटों में भिड़न्त, किया प्रदर्षन

जौनपुर। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बधाई लेने के क्षेत्राधिकार को लेकर किन्नरों के दो गुट आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट व पथराव हुआ। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बाद में एक पक्ष के कुछ किन्नरों ने कोतवाली के बाहर प्रदर्शन भी किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों गुटों के बीच काफी देर तक मारपीट और पथराव चलता रहा। इस दौरान एक किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति पर नियंत्रण पाया। पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

क्या आप हर दिन नाश्ता छोड़ते हैं? जानें शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन रोज ऐसा करने की आदत शरीर पर कई तरह के बुरे असर डाल सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

आजकल व्यस्त लाइफस्टाइल के कारण कई लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के पास समय की कमी होती है, तो कुछ वजन कम करने की कोशिश में नाश्ता नहीं करते, लेकिन नाश्ता दिन की पहली मील माना जाता है। रातभर खाली पेट रहने के बाद शरीर को एनर्जी और जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है।

इसलिए सुबह का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को दिन की शुरुआत के लिए तैयार करने के लिए भी जरूरी माना जाता है। बार-बार नाश्ता छोड़ने की आदत से शरीर पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सुबह का संतुलित नाश्ता अच्छी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा माना जाता है। आइए जानते हैं रोज नाश्ता छोड़ने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, नाश्ते में क्या खाना बेहतर होता है और किन लोगों को नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।

रोज नाश्ता छोड़ने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, रातभर बिना कुछ खाए रहने के बाद सुबह का नाश्ता शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति रोज नाश्ता छोड़ता है, तो कुछ लोगों में दिन की शुरुआत में थकान, कमजोरी या ध्यान लगाने में दिक्कत महसूस हो सकती है।

कई बार बाद में बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से लोग एक साथ ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे संतुलित खानपान बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग बाद में ज्यादा मीठी या तली-भुनी चीजें भी खाने लगते हैं।

हालांकि, हर व्यक्ति के शरीर का असर अलग हो सकता है। अगर किसी को सुबह भूख नहीं लगती, तो वह थोड़ा समय बाद भी हेल्दी नाश्ता कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे दिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व और पर्याप्त एनर्जी मिलती रहे।

किन लोगों को नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए?

बच्चों, टीनेजर, प्रेग्नेंट महिलाओं, डायबिटीज के मरीजों और ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के लिए नाश्ता छोड़ना सही नहीं माना जाता। इन लोगों को दिन की शुरुआत में शरीर को एनर्जी और जरूरी पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप कोई बीमारी, दवा या खास डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो नाश्ता छोड़ने या खाने के समय में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर होता है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए अपनी सेहत के अनुसार खानपान चुनें।

रोज़ नाश्ता छोड़ने के संभावित नुकसान

1. ऊर्जा की कमी और थकान

नाश्ता न करने से शरीर को समय पर ऊर्जा नहीं मिलती। इससे कमजोरी, सुस्ती और पूरे दिन थकान महसूस हो सकती है।

2. ध्यान और याददाश्त पर असर

सुबह भोजन न करने से दिमाग को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जिससे एकाग्रता, सीखने की क्षमता और याददाश्त प्रभावित हो सकती है।

3. अधिक भूख लगना और ज्यादा खाना

नाश्ता छोड़ने वाले लोगों को दोपहर या शाम तक बहुत तेज़ भूख लग सकती है। ऐसे में अधिक कैलोरी वाले या जंक फूड खाने की संभावना बढ़ जाती है।

4. वजन बढ़ने का खतरा

कई लोग सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ने से वजन कम होगा, लेकिन कई अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसा करने से बाद में अधिक भोजन करने की आदत विकसित हो सकती है, जिससे वजन बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है।

5. ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव

विशेषकर मधुमेह या प्री-डायबिटीज़ वाले लोगों में नाश्ता छोड़ने से रक्त शर्करा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

6. मूड पर असर

भूखे रहने से चिड़चिड़ापन, तनाव और मूड में बदलाव महसूस हो सकते हैं। पर्याप्त पोषण न मिलने पर मानसिक कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

नाश्ते में क्या खाना बेहतर होता है?

सुबह के नाश्ते में ऐसी चीजें शामिल करें, जिनसे प्रोटीन, फाइबर और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। ओट्स, अंडे, दही, दूध, फल, साबुत अनाज, अंकुरित दालें, पीनट बटर और मेवे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं, तो पनीर, दही, बेसन या मूंग दाल का चीला भी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा तले-भुने या मीठे फूड्स की बजाय संतुलित नाश्ता चुनना बेहतर माना जाता है। इससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है और शरीर को जरूरी एनर्जी भी मिलती है।

माइग्रेन से जूझ रहे हैं तो न करें ये 5 गलतियां, समस्या हो सकती है गंभीर

माइग्रेन एक ऐसी समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। यह सिरदर्द का एक प्रकार है, जिसमें सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होता है। माइग्रेन के दौरान उल्टी, चक्कर आना और रोशनी से चिढ़ना जैसी कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आमतौर पर माइग्रेन में सिर के दाएं या बाएं हिस्से में तेज दर्द होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो माइग्रेन के रोगियों को नहीं करनी चाहिए।

नींद का ख्याल न रखना

नींद का ख्याल न रखना माइग्रेन के रोगियों के लिए एक बड़ी गलती हो सकती है। पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका शरीर और मन दोनों आराम करते हैं।

अगर आप समय पर सोते और जागते हैं तो आपका सिरदर्द कम हो सकता है।

इसके अलावा दिन में थोड़ी देर की झपकी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस तरह आप ताजगी महसूस करेंगे और आपका माइग्रेन भी काबू में रहेगा।

खाने-पीने में बदलाव न करना

माइग्रेन के रोगियों को अपनी खाने-पीने की आदतों पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप तैलीय, मसालेदार और जंक फूड का सेवन करते रहेंगे तो आपकी समस्या बढ़ सकती है।

इसके बजाय हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और सिरदर्द भी कम होगा।

इसके अलावा पानी अधिक पिएं ताकि आपका शरीर तरलता में रहे और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलें।

पानी की कमी होना

शरीर में पानी की कमी भी माइग्रेन का कारण बन सकती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो इससे आपके सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है।

रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपका शरीर तरलता में रहे और विषाक्त पदार्थ बाहर निकलें।

इसके अलावा नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जो आपके शरीर को पोषण देंगे और सिरदर्द को कम करेंगे।

चिंता और तनाव लेना

चिंता और तनाव लेना भी माइग्रेन के रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है।

अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो इसका असर आपके सिरदर्द पर पड़ेगा। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और सिरदर्द भी कम होगा।

इसके अलावा सकारात्मक सोच अपनाएं और खुश रहने की कोशिश करें ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके और आप स्वस्थ रह सकें।

डॉक्टर की सलाह नजरअंदाज करना

अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता रहता है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है।

खुद से दवा लेना या घरेलू नुस्खे अपनाना सही नहीं होता। डॉक्टर आपकी समस्या का सही कारण बताएंगे और उचित इलाज देंगे। इसलिए समय-समय पर जांच करवाते रहें और उनकी सलाह मानें।

इन गलतियों से बचकर आप अपने माइग्रेन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

डेस्क जॉब करने वाली महिलाएं इन 5 योगासनों को करें अपनी दिनचर्या में शामिल

डेस्क जॉब करने वाली महिलाओं को अक्सर कमर दर्द, गर्दन दर्द और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योग इन समस्याओं से राहत पाने का एक बेहतरीन तरीका है। कुछ सरल और असरदार योगासन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। इन आसनों को आप ऑफिस में भी कर सकती हैं, जिससे आपका शरीर और मन, दोनों स्वस्थ रहेंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसे योगासनों के बारे में बताते हैं।

ताड़ासन

ताड़ासन एक सरल, लेकिन असरदार योगासन है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़ी हो जाएं और दोनों पैरों को आपस में मिला लें।

हाथों को आसमान की ओर सीधा उठाकर उंगलियों को आपस में फंसाएं, फिर धीरे-धीरे सांस लेते हुए पंजों के बल खड़ी हों और शरीर को ऊपर की ओर खींचें।

इस स्थिति में कुछ सेकंड रहने के बाद सांस लेते हुए धीरे-धीरे नीचे आएं। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है और मानसिक शांति देता है।

भुजंगासन

भुजंगासन को सांप की मुद्रा भी कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को कंधों के बराबर लेकर जमीन पर रखें और धीरे-धीरे सांस लेते हुए अपने शरीर को जितना संभव हो सके, उतना ऊपर उठाएं।

इस मुद्रा में कुछ देर रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और गर्दन दर्द से राहत दिला सकता है।

इसके अलावा यह मानसिक शांति भी प्रदान कर सकता है।

बालासन

बालासन

एक आरामदायक मुद्रा वाला योगासन है, जो तनाव मुक्त करने में मदद कर सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठें और माथे को जमीन से सटाएं।

दोनों हाथों को जमीन पर सामने की ओर फैलाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं।

यह आसन पीठ दर्द को कम कर सकता है और मानसिक शांति भी प्रदान कर सकता है।

वृक्षासन

वृक्षासन संतुलन बनाए रखने वाला योगासन है, जिसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़ी हो जाएं। फिर हाथों की मदद से दाएं पैर का तलवा बाएं जांघ पर रख लें।

अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की अवस्था में आ जाएं। इस अवस्था में जितना संभव हो सके उतना देर तक रूकें, फिर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं।

इसके बाद इस प्रक्रिया को विपरीत पैर से दोहराएं।

अधोमुख श्वानासन

अधोमुख श्वानासन को नीचे की ओर देखने वाले कुत्ते की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है।

इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर वज्रासन की मुद्रा में बैठें, फिर सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रखें और गहरी सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं।

इस मुद्रा में शरीर का पूरा भार हाथों और पैरों पर होना चाहिए। कुछ मिनट इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।

अश्लीलता और आईटी एक्ट के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, पिछले 2 साल में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन

केंद्र सरकार ने डिजिटल दुनिया को साफ-सुथरा बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अश्लीलता फैलाने और नियम तोड़ने वाले 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पिछले दो सालों में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है।

आजकल लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और खाली समय में मनोरंजन के लिए हम सभी डिजिटल मीडिया या किसी ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म का रुख करते हैं। लेकिन इंटरनेट की इस असीमित दुनिया में कई बार ऐसा कंटेंट भी परोसा जाने लगा है, जो समाज के मानकों के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। इसे लेकर अब सरकार ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट और सख्त कर दिया है।

हाल ही में लोकसभा में सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी दी है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ। एल। मुरुगन ने बताया कि डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और साफ-सुथरा बनाने के लिए सरकार आईटी नियम, 2021 के तहत लगातार कड़े फैसले ले रही है।

50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कैसे गिरी गाज

पिछले दो सालों के भीतर सरकार ने डिजिटल सफाई अभियान के तहत 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत में पब्लिक एक्सेस के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सख्त कार्रवाई आईटी एक्ट, बीएनएस की धारा 294 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत की गई है। इस फैसले का सीधा संदेश है कि नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ व्यूज बटोरने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए अब डिजिटल दुनिया में मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

आपकी शिकायत सुनने का थ्री-टियर सिस्टम

कई बार दर्शकों को डिजिटल न्यूज या वेब सीरीज में कुछ बेहद आपत्तिजनक लगता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसकी शिकायत कहां दर्ज कराएं। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बेहद मजबूत तीन-स्तरीय (थ्री-टियर) शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है। इसके पहले स्तर पर आपकी शिकायत सीधे पब्लिशर के पास जाएगी। अगर वहां सुनवाई नहीं होती, तो दूसरे स्तर पर पब्लिशर्स की एक सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडी इस मामले को देखेगी। इसके बाद भी समाधान न होने पर तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र (ओवरसाइट मैकेनिज्म) सीधे दखल देगा। इस व्यवस्था ने दर्शक को अपनी शिकायत दर्ज कराने का एक पारदर्शी अधिकार दिया है।

फेक न्यूज से बचाने के लिए बना खास सेल

सोशल मीडिया के दौर में गलत खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। खासकर केंद्र सरकार की योजनाओं या फैसलों के बारे में भ्रामक जानकारियां आम लोगों को गुमराह कर देती हैं। इसे जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने एक 'फैक्ट चेक यूनिट' (FCU) का गठन किया है। यह यूनिट सरकारी विभागों और आधिकारिक स्रोतों से किसी भी खबर की सच्चाई का पता लगाती है। इसके बाद सही और प्रामाणिक जानकारी को विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जनता के लिए पोस्ट किया जाता है।

अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जवाबदेही भी जरूरी

सरकार ने साफ किया है कि इन नए नियमों का मकसद किसी की आवाज दबाना नहीं, बल्कि एक तय जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आईटी नियम 2021 के तहत डिजिटल न्यूज और ओटीटी पब्लिशर्स के लिए एक विशेष आचार संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डिजिटल स्पेस में लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन इस आजादी के नाम पर किसी भी तरह से देश के कानून का उल्लंघन न हो।

आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट को स्थिर रखा, नहीं बढ़ेगी ईएमआई

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी (आरबीआई-एमपीसी) के फैसले का ऐलान बुधवार को गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया। केंद्रीय बैंक ने इस बार भी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा है।

यह लगातार चौथा मौका है, जब आरबीआई एमपीसी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

आरबीआई एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक 3 अगस्त को शुरू हुई थी। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बनी हुई है और इससे कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ब्याज दरों को स्थिर रखना और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ावा देगा।

इससे पहले जून 2026, अप्रैल 2026 और फरवरी 2026 की एमपीसी बैठक में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखा था।

रेपो रेट में आखिरी बार बदलाव दिसंबर, 2025 की आरबीआई एमपीसी की बैठक में किया गया था। इस दौरान रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत से घटाकर 5.25 प्रतिशत कर दिया था।

आरबीआई के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को यथावत रखने के फैसले से सबसे बड़ी राहत उन लाखों लोगों को मिलेगी, जिन्होंने होम लोन, कार लोन या अन्य फ्लोटिंग ब्याज दर वाले लोन लिया हुआ है। रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होने से उनकी मासिक ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ेगी, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही, नए कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए भी ब्याज दरों में तत्काल बढ़ोतरी की संभावना टल गई है। उद्योगों और कारोबारों के लिए भी यह फैसला सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि उनकी उधारी की लागत स्थिर रहेगी और निवेश योजनाओं को गति मिल सकती है। बैंकों के लिए भी ब्याज दरों में अचानक बदलाव का दबाव नहीं रहेगा।

ईंधन कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार जारी रखेगी राहत उपाय

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उससे तेल एवं गैस की कीमतों में आई तेजी के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए आगे भी आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक कदम उठाती रहेगी। सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं पर बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों का बोझ कम से कम पड़े, इसके लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस साल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। यह फैसला पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन कीमतों में आई तेजी के प्रभाव को कम करने के लिए लिया गया था।

मंत्री ने बताया कि शुल्क में इस कटौती के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार को लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि, इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भी बढ़ती लागत के दबाव से कुछ हद तक राहत मिली।

उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क में कमी से सरकारी तेल कंपनियों द्वारा वहन की जा रही आंशिक घाटे की स्थिति को संतुलित करने में मदद मिली, जिससे वे बिना किसी व्यवधान के देश भर में ईंधन की आपूर्ति जारी रख सकीं।

पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार भविष्य में भी ईंधन कीमतों में होने वाली अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरत के अनुसार कदम उठाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे उपायों से देश की वित्तीय स्थिति पर अनावश्यक दबाव न पड़े और राजकोषीय अनुशासन बना रहे।

सरकार की रणनीति राजस्व और खर्च के रुझानों पर लगातार नजर रखने, प्राथमिकताओं के अनुसार सरकारी व्यय में बदलाव करने और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक वित्तीय फैसले लेने पर आधारित है।

मंत्री के अनुसार, इससे सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आने वाली तेजी जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपट सकती है।

उन्होंने कहा कि सरकार बजटीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और राजकोषीय संतुलन के लक्ष्य पर आगे बढ़ने के साथ-साथ ऐसे झटकों का सामना करने की क्षमता भी बनाए रखेगी।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है, जिसमें कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता लाना, सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था बाहरी ऊर्जा झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनेगी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।

इस बीच, सरकार ने जुलाई में रियायती दरों पर मिलने वाले रूसी कच्चे तेल की खरीद भी बढ़ा दी, जो उस महीने देश के कुल तेल आयात का 50 प्रतिशत से अधिक था। यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के बाद खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने और आयात स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा है।

खत्म होगी होर्मुज की टेंशन! ओमान के साथ डील कर रहा ईरान, आखिरी दौर में बातचीत

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने नया दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के लिए ओमान के साथ एक नए समुद्री मार्ग पर सहमति बना ली है। यह डील अब अपने अंतिम स्टेज में है। हालांकि, ईरान ने यह भी साफ किया है कि यह समझौता समुद्री सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और सैन्य गतिविधियां अब भी क्षेत्र में तनाव की सबसे बड़ी वजह हैं।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ नए समुद्री मार्ग को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जियोग्राफिकल कॉर्डिनेट्स पर सहमति बन गई है। हालांकि उन्होंने समझौते की डिटेल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी।

ईरान ने अमेरिका पर सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप

बकाई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस समझौते के बाद भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अब भी अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी कर रखी है। उनका आरोप है कि अमेरिका की आक्रामक सैन्य गतिविधियां और प्रतिबंध समुद्री व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल, ईरान के बयान और पूरे प्रस्ताव परअमेरिका और ओमान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच फिर बंद हो गया था होर्मुज स्ट्रेट

अमेरिका और इजरायल की तरफ से फरवरी में ईरान पर किए गए हमलों के बाद तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट को खोला गया था। हालांकि, जुलाई महीने में दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य टकराव बढ़ गया। इसके बाद ईरान ने फिर से होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी। बता दें कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी (LNG) व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है।

ट्रंप ने ईरान को दी थी कड़ी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार यानी 04 अगस्त को चेतावनी दी थी कि अग हॉर्मुज स्ट्रेट को बहुत जल्द नहीं खोला गया तो ईरान को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि जहाजों की आवाजाही बहाल करने को लेकर बातचीत में प्रगति हुई है। हालांकि ईरान लगातार कहता रहा है कि वह अमेरिका के साथ किसी तरह की सीधी वार्ता नहीं कर रहा है।

ईरान ने कहा- अस्थायी रहेगा नया समुद्री मार्ग

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना से कहा कि ओमान के साथ तय किया गया नया समुद्री मार्ग अस्थायी होगा और दो से चार महीने तक लागू रह सकता है। हालांकि उन्होंने भी इसके संचालन से जुड़ी तकनीकी डिटेल्स जारी नहीं की हैं।

जहाजों से ट्रांजिट शुल्क बना हुआ है सबसे बड़ा विवाद

हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा विवाद ट्रांजिट फीस को लेकर बना हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान चाहता है कि जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाज अपने माल की कीमत का 5 से 7 प्रतिशत शुल्क दें। वहीं ओमान करीब 3 प्रतिशत शुल्क का पक्षधर है, जबकि अमेरिका किसी भी तरह की फीस के पूरी तरह खिलाफ है।रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों पर ईरान का नियंत्रण भी बढ़ सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक, जेट से टकराने से बचा US राष्ट्रपति का हेलिकॉप्टर

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हवाई सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) इस हवाई 'सुरक्षा घटना' की जांच में जुट गया है। राष्ट्रपति का मरीन वन हेलिकॉप्टर वाशिंगटन DC के ऊपर एक-दूसरे विमान के बेहद करीब आ गया था, और यह नियमों के अनुसार सही नहीं था। कहा जा रहा है कि मंगलवार दोपहर जब राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मिलिट्री हेलिकॉप्टर ने व्हाइट हाउस से उड़ान भरी, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) गलती से उत्तरी वर्जीनिया के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों को रोकने में नाकाम रहे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को एक सूत्र ने बताया कि उड़ान के दौरान 'दूरी कम होने' (लॉस ऑफ सेपरेशन) की एक घटना हुई, जिसमें हेलिकॉप्टर और फ्लोरिडा जा रहा एक पैसेंजर जेट, जो कुछ समय पहले ही उड़ा था, नियमों में तय सीमा से अधिक करीब आ गए। हालांकि दोनों विमान आपस में टकराने की स्थिति में नहीं दिख रहे थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने जारी एक बयान में बताया कि वह "मरीन वन की सुरक्षा से जुड़ी एक घटना की जांच कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह कोई खतरनाक स्थिति थी या विमान आपस में टकराने वाले थे।" दूसरी ओर, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, "मरीन वन की उड़ानें दुनिया के कुछ बेहतरीन पायलट उड़ाते हैं, और राष्ट्रपति को किसी भी समय कोई खतरा नहीं था।" हालांकि 2 विमानों के बेहद करीब आ जाने की यह घटना पिछले साल जनवरी में देश की राजधानी के ऊपर एक कमर्शियल एयरलाइनर और सेना के ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर के बीच हुई टक्कर के बाद दूरी से जुड़े नियमों को सख्त किए जाने के बाद हुई है। तब उस हादसे में 67 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने उस घटना को लेकर लापरवाही की बात स्वीकार ली थी। यह हवाई हादसा पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय में अमेरिकी धरती पर हुआ सबसे घातक हादसा था। अब मंगलवार की इस ताजा घटना में अमेरिकी विमानन सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार की घटना में शामिल विमान एम्ब्रेयर E170 जेट था, जिसे अमेरिकन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनवॉय एयर ने फ्लाइट 3742 के तौर पर पेन्साकोला के लिए उड़ाया था। ट्रैकिंग वेबसाइट Flightaware के अनुसार, यह विमान मंगलवार को दोपहर 2:18 बजे रीगन नेशनल पर अपने गेट से निकला, लेकिन इसने तय समय से 34 मिनट की देरी से उड़ान भरी थी और फ्लाइट 16 मिनट बाद दोपहर 2:34 बजे हवा में थी।

अमेरिका को मिलेगा पहला मुस्लिम सीनेटर?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में डेमोक्रेट प्रगतिशील नेता और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब्दुल-अल-सैयद ने मिशिगन राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी सीनेट प्राइमरी चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने पार्टी की सीनियर नेता और सांसद हेली स्टीवंस को कड़े मुकाबले में हरा दिया है. इस जीत को डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर प्रोग्रेसिव खेमे की बड़ी सफलता और इजरायल समर्थक लॉबी AIPAC (अमेरिकन इजरायन पब्लिक अफेयर्स कमिटी) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

अब अल-सैयद अब नवंबर में होने वाले आम चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स का सामना करेंगे. अगर वह यहां चुनाव जीतते हैं तो अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बन जाएंगे. फिलहाल, डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी सीनेट प्राइमरी चुनाव में AIPAC की रिकॉर्ड फंडिंग भी हेली स्टीवंस को हार से नहीं बचा सकी. डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी सीनेट प्राइमरी चुनाव में एक बताया जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नतीजा दिखाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े वर्ग में AIPAC के प्रभाव को लेकर असंतोष बढ़ रहा है. यही वजह है कि अल-सैयद ने जमीनी अभियान और छोटे दानदाताओं के सहारे जीत हासिल की. वहीं, हेली स्टीवंस के समर्थन में AIPAC और उससे जुड़े समूहों ने रिकॉर्ड स्तर पर करोड़ों डॉलर खर्च किए. लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली.

कौन हैं अब्दुल अल-सैयद?

41 वर्षीय अब्दुल अल-सैयद मिशिगन में जन्मे हैं और मिस्र मूल के प्रवासी परिवार से आते हैं. उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से मेडिकल डिग्री और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ में पीएचडी की है. वह पहले डेट्रॉइट स्वास्थ्य विभाग और वेन काउंटी के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग का नेतृत्व भी कर चुके हैं. 2018 में मिशिगन के गवर्नर पद का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि जीत नहीं सके. अब्दुल अल-सैयद की पत्नी का नाम सारा जुकाकू है.वह पेशे से मनोचिकित्सक है. दंपति की दो बेटियां हैं.

अब्दुल अल-सैयद किन मुद्दों पर लड़ा चुनाव?

अल-सैयद ने अपने चुनाव को 'मेडिकेयर फॉर ऑल', सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर लड़ा. उन्होंने गाजा युद्ध के दौरान इजरायल को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता की आलोचना की. उन्हें सीनेटर बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन जैसे प्रोग्रेसिव नेताओं का समर्थन भी मिला.

डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए क्या मायने?

मिशिगन अमेरिका का एक अहम स्विंग स्टेट है और सीनेट की यह सीट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अल-सैयद की जीत को पार्टी के भीतर वामपंथी और प्रोग्रेसिव विचारधारा के मजबूत होते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, आम चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स से होगा. यह मुकाबला अल-सैयद के लिए काफी कड़ा होने जा रहा है.

ईरानी शाहेद मॉडल पर बना भारत का 'काल' ड्रोन, LoC और LAC पर होगी तैनाती

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने 1000 किलोमीटर तक मार करने वाला अपना पहला स्वदेशी वन-वे अटैक ड्रोन बना लिया है। इसका नाम है 'काल'। इसे स्वदेशी रक्षा कंपनी IG डिफेंस ने पूरी तरह भारत में डिजाइन और तैयार किया है। भारत इस वन-वे अटैक ड्रोन को जल्द ही LoC और LAC भी तैनात किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक, भारत सरकार से हरी झंडी मिलते ही इस मारक ड्रोन को मित्र देशों को भी बेचा जाएगा।

'काल' ड्रोन की खासियत:

कंपनी के मुताबिक 'काल' को जल्द ही चीन-पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। दुश्मन के टैंक, बंकर और पोस्ट पर घातक हमला कर सकता है। इसमें ऑटोमैटिक नेविगेशन और सटीक निशाना लगाने वाला सिस्टम लगा है, जिससे यह बिना सैनिकों को खतरे में डाले दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकता है।

क्या है वन-वे अटैक ड्रोन?

काल एक वन-वे अटैक यानी कामिकाज़े ड्रोन है। इसे मिशन के बाद वापस लाने के लिए नहीं बनाया गया। ये सीधे अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसी वजह से इसे लोइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं। कंपनी का कहना है कि ये ईरान के शाहेद-136, रूस के Geran-2 और अमेरिका के LUCAS जैसी कैटेगरी का ड्रोन है। हाल के युद्धों में इस तरह के कम लागत वाले ड्रोन की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है।

रक्षा निर्यात को मिलेगा बूस्ट

IG डिफेंस ने कहा, आने वाले समय में लंबी दूरी के अटैक ड्रोन की जरूरत और बढ़ेगी। काल भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की दिशा में बड़ा कदम है। भारत कम लागत में भरोसेमंद हथियार बना सकता है। काल का निर्यात भारत सरकार की सभी जरूरी मंजूरियों के बाद ही किया जाएगा। सरकार पहले से ही मेक इन इंडिया के तहत रक्षा निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रही है। कंपनी काल के अलावा इंटरसेप्टर ड्रोन, FPV कॉम्बैट ड्रोन, AI स्वॉर्म सिस्टम और काउंटर-ड्रोन सिस्टम पर भी काम कर रही है।

नेशनल हाइवे में खराबी बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से ज्यादा इस छोटे राज्य में हुए एक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट के पूरा होने में हो रही देरी और निर्माण से जुड़े कार्य और उसमें खराबी को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। सरकार ने इन सारे सवालों का जवाब दिया है। पहले ये जान लीजिए कि प्रतापगढ़ी ने कौन-कौन से सवाल पूछे? कांग्रेस सांसद ने पूछा कि पिछले पांच साल में खराब काम के लिए कितने कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या कंसेशनरी पर जुर्माना लगाया गया, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया या काम करने से रोका गया?

हाईवे निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल को मजबूत करने और जवाबदेही पक्की करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? खराब सड़क निर्माण के लिए मुआवज़ के तौर पर कॉन्ट्रैक्टरों से कितनी रकम वसूली गई? इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि क्या सभी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स के लिए थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट जरूरी है और अगर हां, तो इसकी जानकारी क्या है?

सरकार ने सारे प्रतापगढ़ी के सवालों का दिया जवाब

इमरान प्रतापगढ़ी के इन सारे सवालों को जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सभी शिकायतों को ध्यान में रखती है। खराब डिजाइन, कम निगरानी, घटिया सामग्री या ज्यादा सब-कॉन्ट्रैक्टिंग जैसी वजहों से कुछ सड़कें जल्दी खराब होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रोजेक्ट्स में ऐसी समस्याएं मिलीं। इनकी जांच होती है। ठेकेदार और कंसेशनरी को अपने खर्च पर मरम्मत करनी पड़ती है और दोषियों पर कार्रवाई भी होती है।

थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट पर क्या बोली सरकार?

थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट पर सरकार ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स के लिए यह अनिवार्य नहीं है। जरूरत के हिसाब से केस-टू-केस थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिटर लगाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जांच करते हैं कि काम मानक के मुताबिक हो रहा है या नहीं। रोजमर्रा की निगरानी अथॉरिटी इंजीनियर या इंडिपेंडेंट इंजीनियर करते हैं और अधिकारी भी समय-समय पर चेक करते हैं। पिछले पांच साल में कई कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और कंसेशनरी पर कार्रवाई हुई है। इनमें ठेका रद्द करना, जुर्माना, ब्लैकलिस्ट जैसी कार्रवाई शामिल हैं।

सरकार ने ये भी बताया कि खराब काम के लिए ठेकेदारों से जुर्माना और डैमेज वसूला जाता है। मरम्मत ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होती है। अलग-अलग मामलों में लाखों से करोड़ों रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं। ठेका रद्द होने पर सिक्योरिटी भी जब्त हो सकती है। सरकार की तरफ से ये भी बताया कि किस राज्य में कितने एक्शन हुए। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई।

महाराष्ट्र (2024, 2026)

कुल छह प्रोजेक्ट में एक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्टरों पर कुल 3.194 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई। AE पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा। कॉन्ट्रैक्टर और AE के मुख्य कर्मचारियों को 2 प्रोजेक्ट्स में सस्पेंड किया गया। वहीं, साल 2026 में कॉन्ट्रैक्टर पर 75 लाख और AE पर 12.50 लाख का जुर्माना लगा।

उत्तर प्रदेश (2026)

उत्तर प्रदेश में तीन प्रोजेक्ट पर एक्शन हुआ, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया गया।

बिहार (2022, 2023 और 2024)

बिहार में 5 प्रोजेक्ट में एक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्टर के मेन आदमी और AE/IE को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा 2023 में कॉन्ट्रैक्टर पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। वहीं, 2024 में कॉन्ट्रैक्टर के मेन आदमी को सस्पेंड किया गया।

केरल (2024, 2025)

कुल 8 प्रोजेक्ट में एक्शन हुआ। 2024 में एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पैसे से मरम्मत करवाई। वहीं, सात अन्य प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर और AE/IE के मुख्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। वहीं, 2 प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्टर और AE/IE को डिबार किया गया।

अभिनय को लेकर बहुत लालची हूं, जैस्मिन भसीन ने अपने जुनून पर की बात

अभिनेत्री जैस्मिन भसीन इन दिनों एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वह जहां एक तरफ स्टंट-आधारित रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में खतरनाक टास्क करती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी आगामी पंजाबी फिल्म जुदा की रिलीज को लेकर भी उत्साहित हैं। अलग-अलग भाषाओं और प्लेटफॉर्म पर काम करने के अपने अनुभव को लेकर जैस्मिन का कहना है कि अभिनय उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा जुनून है।

इसलिए वह हर नए मौके को स्वीकार करना चाहती हैं और खुद को अलग-अलग भूमिकाओं में आजमाना चाहती हैं। जैस्मिन भसीन ने अपने करियर और अभिनय के प्रति अपने लगाव को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि अभिनय को लेकर मैं बहुत लालची हूं क्योंकि यह मेरा सबसे बड़ा प्यार और मेरा जुनून है।

मेरे सामने चाहे कुछ भी आए, मैं हमेशा उसे एक्सप्लोर करना चाहती हूं और अपना पूरा योगदान देना चाहती हूं। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि काम किस भाषा या प्लेटफॉर्म पर है, मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मुझे कुछ नया करने और सीखने का मौका मिले। उन्होंने कहा, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और आभारी महसूस करती हूं कि मुझे अलग-अलग भाषाओं और प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिल रहा है।

अलग-अलग तरह के दर्शकों से जुड़ना मेरे लिए बहुत खास अनुभव है। अभिनेत्री ने कहा, एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना आसान नहीं होता। यह सफर व्यस्त जरूर है लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे हर दिन में कोई नई चुनौती हो। एक कलाकार के तौर पर मैं हमेशा खुद को आगे बढ़ाना चाहती हूं और कुछ नया सीखना चाहती हूं।

बिग बॉस 20 प्रोमो रिलीज: फैंस को सोच में डाल गए सलमान खान, बोले- जो करण अर्जुन में हुआ था, वो अब...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर अपने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस से धमाका करने आ रहे हैं। बॉस सीजन 20 का टीजर जारी हो गया है। जियो-हॉटस्टार ने आज सोशल मीडिया पेज पर बिग बॉस 20 का टीजर रिलीज कर दिया है। बिग बॉस 20 शुरू होने में अब एक महीना बचा है और इससे पहले शो के टीजर ने धमाका मचा दिया है। सलमान खान ने टीजर में कुछ ऐसा बोला है, जिसे जानने के लिए सब बेताब है। प्रोमो में सलमान ने फैंस ऐसा ट्विस्ट दिया है कि लोग अब जानने की कोशिश में लगे हैं आखिर शो में ऐसा क्या होगा।

बिग बॉस 20 के निर्माताओं ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान खान और घोड़े को दिखाते हुए एक नया प्रोमो शेयर किया। कैप्शन में लिखा है, एक से भले दो।। बिग बॉस 6 सितंबर से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर शुरू हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान काले रंग की पैंट, काली टी-शर्ट और बिना आस्तीन की काली जैकेट पहने दमदार एंट्री करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक्टर घोड़े को अस्तबल से बाहर लाते हुए कहते हैं, जो करण अर्जुन में हुआ था, वो अब बिग बॉस में होगा। थतास्तु।

बिग बॉस 20 के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा था, बिग बॉस का हर सीजन एक नया खेल, नए समीकरण और अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेकर आता है। लेकिन इस सीजन में एक ऐसा रहस्य छिपा है, जो इसे पहले देखे गए किसी भी सीजन से अलग बनाता है। पहला संकेत पहले ही मिल चुका है, बस आपको इसे दो बार देखना होगा। टीजर तो बस शुरुआत है, और मैं दर्शकों के बिग बॉस हिंदी सीजन 20 शुरू होने पर सुरागों को जोड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

बिग बॉस 20 का प्रोमो ऑनलाइन वायरल होते ही, नेटिजन्स सलमान और मेकर्स के करण अर्जुन ट्विस्ट के पीछे के मकसद का अंदाजा लगाने में जुट गए हैं। कुछ फैंस का मानना है कि शाहरुख खान रियलिटी शो में मातृभूमि एक्टर सलमान खान के साथ नजर आएंगे, वहीं कुछ का अनुमान है कि यह शो के पुराने कंटेस्टेंट्स की वापसी (पुनर्जन्म) हो सकती है।

सलमान और शाहरुख खान की बात करें तो, दोनों ने पहली बार 1995 में आई पुनर्जन्म पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म करण अर्जुन में एक साथ काम किया था। इसके बाद, वे कुछ कुछ होता है और हम तुम्हारे हैं सनम में भी साथ नजर आए थे। तब से, उन्होंने एक-दूसरे की फिल्मों जैसे टाइगर 3, पठान, जीरो और ट्यूबलाइट में कैमियो किया है।

बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर होगा। पिछले कुछ सीजन के उलट, इस साल सेट का डिजाइन फिल्म निर्माता ओमंग कुमार के बजाय आर्ट डायरेक्टर कंचन और रूपाली ने किया है। हालांकि अभी तक कंटेस्टेंट्स के नाम की लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन माही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबैर, फैसल शेख (मिस्टर फैसु), सुनील पाल, निया शर्मा, पर्ल वी पुरी और शोविक चक्रवर्ती जैसे सेलेब्स के नाम संभावित कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं।

राम कपूर ने किसी को असहज महसूस नहीं कराया, किसिंग विवाद पर बोलीं आकांक्षा चौधरी

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे रिएलिटी शो लॉक अप 2 से निकलने के बाद भी आकांक्षा चौधरी चर्चा में बनी हुई हैं। इस बीच उन्होंने शो में महिला कंटेस्टेंट्स के माथे और गालों पर किस करने की राम कपूर की आदत को लेकर मचे विवाद के बीच उनका समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कभी भी राम कपूर को किसी को असहज महसूस कराते हुए नहीं देखा। आकांक्षा ने कहा कि वह समझती हैं कि इंडस्ट्री में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन राम कपूर की नीयत कभी भी गलत नहीं थी। उन्होंने कहा, जाहिर है, मैं मानती हूं कि इंडस्ट्री और बाहर भी ऐसा बहुत होता है। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह रही। लेकिन क्योंकि मैं शो में थी और राम सर से रोज बात करती थी। सीक्रेट रूम में भी मैंने श्रेया की राम सर के बारे में कही हर बात सुनी थी। असल में ऐसा कुछ नहीं था। राम सर ने किसी को भी असहज महसूस नहीं कराया।

घर के अंदर हुई एक बातचीत को याद करते हुए उन्होंने बताया कि श्रेया कालरा ने एक बार शिल्पा शिंदे के सामने कहा था कि राम कपूर उन्हें उनके अपने पिता से भी ज्यादा किस करते हैं।

उन्होंने कहा, जब मैं सीक्रेट रूम में थी, तो मुझे लगता है कि श्रेया ने शिल्पा शिंदे के सामने कहा था कि राम सर मुझे मेरे पिता से भी ज्यादा किस करते हैं। लेकिन तब शिल्पा जी ने कहा, नहीं, नहीं, वह ऐसा नहीं करते हैं।

आकांक्षा ने आगे कहा कि श्रेया ने खुद साफ किया था कि उनका मतलब गलत तरीके से नहीं था। उन्होंने कहा, श्रेया ने कहा था, जाहिर है, मैं उस तरह से नहीं कह रही हूं। मेरा मतलब वैसा नहीं है। मैं बस यह कह रही हूं कि वह बार-बार ऐसा करते हैं। तो वह इस बारे में बहुत सहज थीं।

वहीं, राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर जब शो में आई थीं, तो उन्होंने सभी से राम कपूर के व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा, अगर इनसे कोई गलती हो गई हो या इन्होंने आपको असहज किया हो तो मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूं। हालांकि, गौतमी ने बचाव करते हुए यह भी कहा कि उनके पति का स्वभाव ऐसा ही है, वे टेडी बेयर की तरह हैं और उनका इरादा गलत नहीं था।

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि राम कपूर हाल ही में सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार हुए थे। शो के कुछ क्लिप वायरल हुए थे जिनमें वे महिला कंटेस्टेंट्स का माथे और गालों पर किस करते हुए दिखे थे। कई दर्शकों का आरोप था कि इन हरकतों से कुछ कंटेस्टेंट्स असहज महसूस कर रही थीं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com